प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ..सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-07, अंक - 10 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरूवार 28 नवम्बर 2024 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

एक पीढ़ी का पाखंड, अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है।

हेलन केलर

रेवड़ियां मीठी लगती है...

एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे... नारा हिट

माही की गूंज, संजय भटेवरा।

झाबुआ। हाल ही में संपन्न दो राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामो में एक बात समान रही और वो ये की दोनों ही राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन ने न केवल सत्ता में वापसी की वरन पहले से ज्यादा मजबूती भी हासिल की। झारखंड में जहां सत्तारूढ़ गठबंधन ने 9 सीटे ज्यादा जीती। तो महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुती ने पिछले चुनाव की अपेक्षा लगभग 9 प्रतिशत ज्यादा वोट हासिल कर 288 सदस्यीय विधानसभा में 234 सीटे जीतकर ऐतिहासिक व अप्रत्याशित बहुमत हासिल किया। दोनों ही राज्यों में महिलाओं के लिए लागू की गई लाड़की बहिना व मईया सम्मान योजना ने ठीक वैसी ही भूमिका निभाई जैसी पिछले वर्ष मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना ने निभाई थी। इस योजना के बाद कई सीटों पर महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत भी बड़ा है। और जाहिर तौर पर यह बड़ा हुआ मतदान सत्ताधारी के पक्ष में ही गया। जहां इस योजना में महिलाओं को प्रतिमाह एक निश्चित रकम मिल रही थी। हालांकि इसी प्रकार की योजनाओं की घोषणा विपक्षी दलों ने भी की थी लेकिन महिलाओ ने आश्वासन भी अपेक्षा असलियत को प्राथमिकता दी।

इस योजना पर तमाम बुद्धिजीवी वर्ग आपत्ति जताकर इसे घातक बता रहे थे और कह रहे थे कि, मुफ्त की रेवड़ी अन्ततः सरकार के लिए बहुत महंगी साबित होगी। लेकिन मतदाताओं ने अपने मत से यह साबित कर दिया कि, रेवड़ी बांटने वाले के लिए महंगी साबित हो सकती है लेकिन बहुत मीठी लगती है।

अब आगे क्या...?

निश्चित रूप से हर चुनाव में मतदाता एक संदेश देते हैं और जो राजनीतिक दल उस संदेश को समझकर अपनी रणनीति में परिवर्तन कर लेता है आगे के चुनाव में उसकी राह आसान हो जाती है। लोकसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आईना दिखा दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबकी बार चार सौ पार व मोदी है तो मुमकिन है नारे को खारिज कर दिया था। जिसके बाद हार से सबक लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति बदली व जनता का भरोसा जीतने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस, नतीजो से उत्साहित होकर आत्ममुग्ध हो गई। ऐसे में जनता ने एक बार फिर मोदी के नारे 'एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे' पर विश्वास दिखा कर सत्ता की चाबी भाजपा के हाथ में सौंप दी।

इन पूरे चुनाव में राज्य की दो प्रमुख पार्टिया अपने-अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी। यही नहीं असली बनाम नकली (शिवसेना व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) की लड़ाई भी लड़ी गई और जनता ने अपने मत से साबित कर दिया कि, कौन असली है तथा कौन नकली।

जहां तक झारखंड चुनाव परिणामो का सवाल है तो, यहां का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत छवि पर लड़ा गया था। कांग्रेस के लिए यहां यह संतोष की बात रह सकती है कि, वो पिछली सरकार की तरह ही इस सरकार में सहयोगी व भागीदार की भूमिका में रही है। यहां भी मईया सम्मान योजना एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हुआ है और लोगों ने चल रही योजना पर ही अपना विश्वास जताया और आश्वासनों को खारिज कर दिया।

दलबदल पर लगेगा विराम...?

सत्ता का स्वाद सभी चखना चाहते हैं और इसके लिए सिद्धांतों और आदर्शों को तिलांजलि दे दी जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में छठी बार विधानसभा जीतकर विधायक बनने वाले विजयपुर के विधायक रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की सदस्यता ले ली। नियमों के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस के विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया और भाजपा सरकार ने उन्हें इनाम स्वरूप बिना विधायकी के भी मंत्री पद से इस उम्मीद से नवाज दिया कि, उपचुनाव में उन्हें भाजपा के टिकट पर विधायक बना देंगे। लेकिन कहते हैं कि, लोकतंत्र में पब्लिक इज ऑलवेज राइट यानी जनता ही हमेशा सही होती है। और विजयपुर की जनता को अपने विधायक का दल-बदल रास नहीं आया और उन्होंने रामनिवास रावत को घर बिठाकर कहावत ÷चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर बैठ गए÷ चरितार्थ कर दिया। यानी विधायक से मंत्री बनने गए थे तो विधायक भी नहीं रह पाए। इसी प्रकार कांग्रेस की एक और महिला विधायक ने भी लोकसभा चुनाव में भाजपा का दुपट्टा पहन लिया था। लेकिन अभी तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी व विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया। वो इन परिणामों के बाद अपने निर्णय पर पूर्न विचार कर सकती है। हालांकि कांग्रेस अब उन्हें अपना विधायक नहीं मान रही है और सदस्यता समाप्ति को लेकर वैधानिक कार्यवाही कर रही है। ऐसे में ये महोदया मझधार में है इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति में है। जनता ने अपने वोट से साबित कर दिया कि, वो आंख मूंद कर वोट नहीं करती है। भाजपा का चुनाव चिन्ह जीत की गारंटी नहीं है... ! जितने के लिए आपको जनता का विश्वास जीतना ही होगा। ऐसे में अब उन नेताओं के सुर भी बढ़ सकते हैं जो पाला बदलने का अवसर देख रहे थे। वहीं सरकार को भी जनता ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि, सरकार के सभी फैसले सही नहीं होते हैं... !

उपचुनाव में सत्तारूढ़ दलों का दबदबा

इन चुनावो के साथ ही विभिन्न राज्यों में उपचुनाव भी हुए। जिसमें लगभग सभी जगहो पर सत्तारूढ़ पार्टियों ने अपना दबदबा कायम रखते हुए विपक्ष पर बढ़त बनाई। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की रही, जहां लोकसभा चुनावो में अपेक्षाकृत निराशाजनक परिणामो के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दाव पर लगी थी और उनका नारा ÷बटेंगे तो कटेंगे÷ पूरे देश में चर्चित रहा है। यहां भाजपा ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया। राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन मध्य प्रदेश में आंकड़ा 50-50 रहा। लेकिन बुधनी विधानसभा जो की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट रही वहां भाजपा की जीत का मार्जिन बहुत अधिक कम होना चर्चा का विषय रहा। तो प्रदेश सरकार के वन मंत्री की हार देश भर में चर्चा का केंद्र बिंदु रही है। विजयपुर की प्रतिष्ठापूर्ण सीट पर कांग्रेस की विजय व बुधनी विधानसभा में जीत का अंतर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की पहली परीक्षा थी। जिसमें वे जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे और विजयपुर भी विजय कांग्रेस में नया जोश पैदा कर सकती है।

फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून से लिखा पत्र

मुंबई, एजेंसी।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित हो गए हैं, लेकिन महायुति अब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। बीजेपी ने इस पर निर्णय लेने के लिए पर्यवेक्षक भेजने का निर्णय लिया है, जो विधायकों से रायशुमारी करेंगे और फिर मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। उधर, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए औरंगाबाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने खून से एक पत्र लिखा है।

वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शिंदे 28 जून 2022 से 26 नवंबर 2024 तक मुख्यमंत्री रहे। विधानसभा का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया है, और अब नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के रूप में लगभग तय हो चुका है। फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद नई सरकार में दो उपमुख्यमंत्री होंगे, जिनमें एक एनसीपी से अजित पवार और एक शिवसेना से शिंदे हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, नई सरकार का एजेंडा तय करने के लिए तीनों दलों की एक समिति बनाई जा सकती है, जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे करेंगे। हालांकि, शिवसेना प्रवक्ता कृष्ण हेगड़े ने इस पर कोई पुष्टि नहीं की है।

नेता विपक्ष को लेकर महा विकास आघाड़ी (एमवीए) संयुक्त रूप से दावा पेश कर सकती है। विधानसभा चुनाव में किसी भी विपक्षी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष के लिए जरूरी सीटें नहीं मिलीं। नियमानुसार, विधानसभा सीटों का कम से कम 10 प्रतिशत हासिल करने वाली विपक्षी पार्टी को यह पद मिलता है। यदि कई पार्टियों ने ज्यादा सीटें जीतीं तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को यह पद दिया जाता है। इस बार एमवीए संयुक्त रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने का दावा कर सकती है, और इसके लिए राज्यपाल को पत्र भेजा जाएगा, जिसमें प्री-पोल गठबंधन का तर्क प्रस्तुत किया जाएगा।

अविकसित शव मिला

माही की गूंज,काकनवानी। नरेश पंचाल

मंगलवार शाम 6 बजे काकनवानी में बाजार के पीछे वाली गली में एक अविकसित बच्चा देखा गया। जिस पर मुकेश गेहलोत के मकान के पीछे होने से पुलिस को कॉल किया गया।

तत्काल पुलिस के आने पर उस भ्रूण को पैकिंग कर ले जाया गया। इसके पश्चात बुधवार सुबह को भ्रूण का पीएम किया गया। जिसमें नवजात भ्रूण शिशु का वनज, उम्र एवं लिंग परीक्षण भी किया गया। डॉक्टर अनुसार 290 ग्राम का भ्रूण है एवं 14 से 16 सप्ताह का बालक है। पीएम के पश्चात डॉक्टर बाबरिया से इस विषय में जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि, कभी-कभी महिलाओं को काफी दिक्कतें होने के कारण दो-तीन माह में बिना दवाई गोली के भी गर्भपात हो जाता है। जिस स्थान पर यह अविकसित बच्चा मिला है उस स्थिति में देखने पर पता लगता है कि, इस भ्रूण का इसी स्थान पर जन्म हुआ है और उसे यही छोड़कर चले गए हैं, यह कहीं और से लाकर डाला हुआ नहीं है।

मामले में पुलिस ने अज्ञात नाम से एफआरआई दर्ज़ कर जांच शुरू कर दी गई है।

सोशल मीडिया और ओटीटी पर अश्लील कंटेंट रोकने के लिए बनेगा कानून...

नई दिल्ली।

लोकसभा में बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है।

उन्होंने बताया कि पहले सामग्री को प्रकाशित करने से पहले संपादकीय जांच होती थी, जिससे अश्लीलता पर नियंत्रण रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मंत्री ने बताया कि सरकार ओटीटी सामग्री को नियंत्रित करने के लिए नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है। पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने कहा था कि सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोकने के लिए जरूरी नियम बनाए जाएंगे। अदालत ने भी इस मुद्दे पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत बताई थी।

दलित युवक की हत्या पर कांग्रेस का हमला, कमलनाथ ने सुरक्षा की मांग की

भोपाल।

शिवपुरी में दलित युवक नारद जाटव की हत्या के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था में नाकाम रहने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने विपक्ष पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने की मांग की है। इंदरगढ़ गांव में पानी लेने को लेकर हुए विवाद में सरपंच पदम धाकड़ के परिवार ने नारद जाटव को लाठियों से बेरहमी से पीटकर मारा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे कांग्रेस ने सरकार पर हमले के रूप में पेश किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

कमलनाथ ने सीएम से प्रदेश में दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की है, जबकि सीएम ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।

फर्जी कॉलोनी की जांच में पुराना रिकॉर्ड देखता प्रशासन तो हो जाता मामला उजागर

शिकायत के बाद शासकीय भूमि की बिक्री करने के मामले में हुई कार्रवाई

जमीन की खरीदी बिक्री पर भी रोक, आखिर कब प्रशासन करेगा भूमि को मुक्त

माही की गूंज , पेटलावद। राकेश गेहलोत

क्षेत्र में 8 से 10 वर्षों में भूमि की रजिस्ट्री तथा नामांकन प्रक्रिया करने के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उसका मूल कारण क्षेत्र के अंदर भू-माफियाओं की सक्रियता बड़ी है। देखा जाए तो यह भू-माफिया तहसील कार्यालय तथा कई स्थानों पर अपनी दुकानदारी वेंडर के मार्फत जमाए बैठे हैं। तथा वेंडर की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। अधिकतर विवादित भुमि के मामलों में भी इनकी सक्रियता देखी जा रही है। विवादित भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण की बात करें तो शासन की ऐसी कई बैस कीमती भूमि जो गोचर, गोया ,चरनोई, मरघट, बयड़ी और शासन से प्राप्त पट्टेदार की भूमि शासन से उद्योग पर ली गई लीज प्राप्त भूमि है। जिसको बेचा और खरीदा भी नहीं जा सकता है। ऐसी शासन की भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण वर्ष 1956-57 से लगाकर भू-राजस्व संहिता वर्ष 1959 लागू होने के बाद के रिकॉर्ड नहीं देखते हुए की जा रही है। जबकि किसी भी रजिस्ट्री और नामांतरण के मामले में कलेक्टर तथा एसडीएम और तहसीलदार की अनुमति के बगैर पुराने रिकॉर्ड देखें ही धड़ल्ले से क्षेत्र में रजिस्ट्री व नामांतरण कीया जा रहा है।

मामलाः ग्राम बामनिया से है जुड़ा, फर्जी कालोनी पर उठाई गूंज ने आवाज

ग्राम बामनिया पटवारी हल्क [illegible] नंबर-1 [illegible] की 19-13 रकबै की भुमि वर्ष-1957-58 मे शासकीय मद की भूमि रिकॉर्ड अनुसार दर्ज रही थी। जिसके बाद उक्त सर्वे नंबरों की भूमि कालम नंबर 4 जुराबअली आत्मज अब्दुलअली बोहरा(महाजन) समुदाय निवासी दाहोद लगायत संवत खसरा पांचशाला 2015 वर्ष - 1957-58- व कालम नंबर 12 में लक्कड़पीठा के नाम से दर्ज भुमि रही थी। वहीं रिकॉर्ड मे तुराबअली बोहरा के उपर कालम नंबर 1 में सर्वे नंबरों में रकबा 0, शासकीय मद, नीचे बालेश्वर दयाल सर्वे नंबरों में रकबा-0-40 शासकीय मद पर दर्ज थी। खसरा खाता रिकॉर्ड में कालम नंबर 12 में दर्ज 1 टापरा, 2 बबुल, 1 कुआं, 1 लक्कड़पीठा, के साथ ही कॉलम नंबर 18 में जगन्नाथ पिता देवी सिंह राजपूत अतिक्रमणकारी का भी नाम दर्ज था। जिसके द्वारा ही रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई थी। ग्राम बामनिया का सेटलमेंट 1974 में उक्त शासन मद की भूमि हीरालाल अग्रवाल के नाम चढ़ गई थी। उक्त भूमि के एक भाग में बिना किसी अनुमति के फर्जी कालोनी काटी गई। जहा जिनिंग फेक्ट्री चलाई जा रही है। उसे हटा कर यहां कॉलोनी बता कर प्लाटिंग की गई । कॉलोनी की शिकायत के बाद माही की गूंज में मय प्रमाण के खबरे सीरियल से प्रकाशित की गई। लेकिन प्रशासन ने भूमि का पुराना रिकॉर्ड देखने की बजाए मामले को गोलमोल कर हवा में उड़ा दिया ।

निरंतर...पेज 2 पर

... पेज 1 से निरंतर समाचार

फर्जी कॉलोनी का मामला: तहसीदार ने निकाली थी विज्ञप्ति, हुई थी आपत्ति दर्ज

उक्त सर्वे नंबर की भूमि रजिस्ट्री नामांतरण के संबंध में तहसीलदार पेटलावद द्वारा ममता पति अशोक कुमार अग्रवाल निवासी बामनिया हाल मुकाम रतलाम के द्वारा ममता पति जयंतीलाल भंडारी निवासी पेटलावद को भूमि बेचने के संबंध में तहसील न्यायालय से विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसको लेकर आरटीआई एक्टिविटीज और आमजन के हित में पक्ष रखने वाले

श्रवण कुमार मालवीय द्वारा जनहित मुद्दे को लेकर आपत्ती दर्ज करवाई गई थी। जिसमें तहसील न्यायालय पेटलावद द्वारा गंभीर प्रकरण को लेकर उपर न्यायालय में जाने के आदेश पारित किए गए थे। जनहित याचिका अपील प्रकरण में पक्ष तथा विपक्ष की सुनवाई को लेकर लगातार एसडीएम न्यायालय पेटलावद द्वारा सुनवाई की गई। जनहित मुद्दे को लेकर आरटीआई एक्टिविटीज द्वारा अपनी पैरवी न्यायालय के समक्ष खुद ने की। तर्क और बहस के समय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के वकील ने अर्चना की और से बहस की थी। उक्त प्रकरण में न्यायालय एसडीएम द्वारा शासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जनहित मुद्दे को लेकर पेटलावद क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय अपने पारित आदेश में दिया जो कहीं ना कही नीव का पत्थर साबित होगा ।

नगर विकास में बड़ी भूमिका हो सकती हैं सरकारी भूमि

शासकीय भूमि मामले में जनहित याचिका लगाने का मूल उद्देश्य ग्राम बामनिया बड़े क्षेत्र में निवास करता है जनजाति बहुल क्षेत्र में इस भूमि का उपयोग हर जाति के गरीब व्यक्ति को रहने के लिए भूमि मिले, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए कॉलेज खुले, अच्छा अस्पताल बने खेल स्टेडियम का निर्माण हो, सरकारी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित किया जाय इस संबंध में ही जनहित याचिका दायर की गई थी। उक्त सरकारी भूमि यदि सरकार के पास आती है तो नगर विकास को पंख लग सकते हैं ।

इन 13 लोगों के नाम दर्ज है भूमि, आदेश के बाद भी राजस्व रेकॉर्ड में सुधार नही

ग्राम बामनिया पटवारी हल्का नंबर 1 की 19 -13 बड़े रकबै की शासकीय भूमि अग्रवाल दंपति के नाम दर्ज भूमि रही है। जिसमें दशरथ लाल पिता हीरालाल अग्रवाल, पुत्र मनोज पिता दशरथ अग्रवाल, यशवंत पिता नंदलाल अग्रवाल, गौरव अग्रवाल प्रेमलता अग्रवाल, सावित्री देवी अग्रवाल, आशा देवी अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल, मोहनलाल पिता हीरालाल अग्रवाल, शैतनमल पिता हीरालाल अग्रवाल, चंद्रकांता अग्रवाल, नितिन पिता मोहनलाल अग्रवाल, अर्चना पति अशोक कुमार अग्रवाल, शशि बाला अग्रवाल, समस्त निवासी गण नारेला रोड बामनिया तहसील पेटलावद जिला झाबुआ सहित रतलाम मे निवास करते हैं। उक्त भूमि शासकीय घोषित होने के बाद भी राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भूमि राजस्व रिकार्ड में शासकीय दर्ज नही की न ही भूमि का समतलीकरण किया गया ।

उप रजिस्ट्रार को आदेश, बिक्री-खरीदी पर रोक

उक्त सर्वे नंबर और पेकी की भूमि पर धारा 165 मे हो रही रजिस्ट्री के संबंध मे उप रजिस्ट्रार पेटलावद को एसडीएम न्यायालय पेटलावद द्वारा आदेश जारी किया गया कि संबंधित भूमि पर हो रही रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाए तथा इसका सख्त से सख्त पालन किया जाए।

अवैध कॉलोनी सहित जिनिंग फैक्ट्री भी उक्त भूमि में है शामिल

संबंधित प्रकरण में हुए आदेश के परिपालन में ग्राम बामनिया पटवारी हल्का नंबर 1 की 19 -13 बड़े रकबै की शासकीय भूमि अग्रवाल दंपति ने जिनिंग फैक्ट्री खोलने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी खड़ी कर छोटे बड़े भूखंडों के रूप में विक्रय कर दी है। और लगातार संबंधित भूमि के ऊपर कई दुकानें भी संचालित हो रही है। इसके साथ ही खाली पड़ी भूमियों की बिक्री भी अग्रवाल दंपति द्वारा की जा रही थी। जिसका सीमांकन होना अभी शेष है इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि इस रकबै के अलावा आसपास खाली पड़ी सरकारी भूमि पर कितनी रजिस्ट्री इनके द्वारा करवाई गई है।

खरीद-फरोख्त आज भी जारी

भूमि स्वामी बन कर बैठा अग्रवाल परिवार इस बात से अनभिज्ञ नही है कि भूमि आज नही तो कल शासकीय निकलने पर हाथ से निकल सकती हैं । उक्त भूमि पर काबिज अग्रवाल बन्धुओ ने इस भूमि का ज्यादातर हिस्सा कई लोगो को विक्रय कर दिया है । अनुविभागीय न्यायालय से भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगने के बाद अनुबंध पर क्रय-विक्रय किया जा रहा है एवं उक्त भूमि पर निर्माण कार्य भी धड़ल्ले से जारी है जिस पर प्रशासन की कोई नजर नही। तहसीलदार निगवाल भी इस भूमि पर निरक्षण करने जा चुके हैं लेकिन कार्यवाही वही रुकी हुई ।

हाईकोर्ट में मामला

करोडों की बेशकीमती भूमि को अपने कब्जे में रखने के लिए भूमाफियाओ द्वारा न्यायालय के लचीलेपन का फायदा उठा कर इस प्रकार के मामलों को न्यायालय की प्रक्रियाओं में उलझा कर लंबा समय निकाल देते हैं और अपने सेटिंग के अधिकारीयो के आने पर खेल कर न्यायालय में लीपा पोती की कोशिश की जाती है । इस मामले में शासकीय भूमि पर काबिज पक्ष उच्च न्यायालय की शरण मे गया हैं । वही आरटीआई कार्यकर्ता श्रवण कुमार मालवीय ने बताया कि इस प्रकार के मामले में दूसरा पक्ष न्यायालय में मामले उलझता है इस लिए मेरे द्वारा पूर्व से ही हॉइ कोर्ट इंदौर के वी एट लगा रखी है ताकि किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी होने से पूर्व शासन ओर मुझ याचिकाकर्ता का पक्ष सुना जाये।

पलायन से अंचल के बच्चों में कुपोषण का बढ़ता ग्राफ...

माही की गूंज, झाबुआ।

जनजातिय लोगों के लिए पलायन एक ऐसा अभिशाप है, जिसमें व्यक्ति अपनी आजीविका को चला तो रहा है परंतु सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और शारीरिक विकास में पिछड़ता जा रहा है। और शासन के साथ प्रशासन अपनी जिम्मेदारी के झोले में छेद किए हुए बगल में देखते हुए, शहरी एवं ग्रामीण विकास की गंभीर बात करके पीठ थपथपा रहें हैं। पैसा कमाने के लिए ग्रामीण साथ अपने कुछ राशन लेकर जाते है और अपने कर्ज को खत्म करने के उद्देश्य से भी, किंतु वो गोल चक्र पुरा ही नहीं कर पाते और समय समाप्त हो जाता है। इस दिशा में वो अपने बच्चों के भविष्य की बलि चढ़ा रहें हैं। जिसका उनको आभाष भी नहीं है और जिसके फल से वे अनभिज्ञ भी है। मजबूरी में घर त्यागने वाले मजदूर अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित तो कर ही रहें हैं साथ ही जाने-अंजाने उनके पोषण के साथ भी खिलवाड़ कर उनको कुपोषित बना रहे हैं। परिवार के जीवन यापन की विवशता की गंभीरता इतनी होती है कि, वे अपने दुधमुंहे बच्चें को साथ ले जाते हैं और मजदूरी के भंवर में बच्चा कुपोषण के घेरें में आ जाता है।

पलायन के पथ पर बढ़ते इन लोगों की दुर्दशा की जिम्मेदार सरकार और उनकी बनाई गई नीतियों पर प्रशासन की बेरुखी के साथ बेढंग चाल का चलन है। योजनाओं से वंचित किसान अपनी सुखी भूमि को देखते-देखते आँखों को नम कर लेता है, और आसमान की ओर देखकर दूर प्रदेश में अपने बच्चों के साथ पेट की अगन को शांत करने के लिए चल देता है। लेकिन उसी के साथ उसके छोटे-छोटे बच्चें दुख, दर्द के साथ बेवजह की यातनाएं सहते-सहते कुपोषण का शिकार होकर वो शारीरिक दुर्बलता के वश में आ जाते हैं।

ग्राउंड रिपोर्ट देखे तो शासन-प्रशासन के सारे दावे यहां निष्क्रिय दिखाई देते है। क्योंकि पलायन की वजह से जनजातिय समाज का सामाजिक विकास रुक रहा है। उसी के साथ उनका आर्थिक विकास भी गर्त में जा रहा है। फिर जागरुकता और शेक्षणिकता के स्तर में भी इसी पलायन के कारण से नीचे गिरते जा रहा है, और विवशता के वश में होते पलायन से वे अपने और बच्चों के शरीर के साथ खिलवाड़ कर कुपोषण के गंदे कुएं में झौंक रहें हैं।

आंकड़ो के अनुमान से करिब एक लाख बच्चें अपने माता-पिता के साथ पलायन के शिकार होते हैं और उनमें से लगभग 1500 से अधिक बच्चें अति कुपोषण की चपेट में आते हैं। और तकरिबन 9 हजार बच्चें कम वजनी पाए जाते है। इस तरह पलायन किसी डायन की भांती समाज के बच्चों को क्षति पहुंचाती जा रही है।

अगर अपने ही अंचल में सुविधा के साथ रोजगार मिलने लग जाए तो ये लोग यहां रहकर गुजर-बसर कर सकेगे। साथ ही इसके उन बच्चों का भविष्य भी नहीं बिगड़ेगा जिनको पलायन का दंश झेलना पड़ रहा है। शासन के शक्तिहीन दावो में बुनियादी प्राथमिकता भी यदि आ जाए तो कुपोषण से पीड़ित परिवार रोग से प्रताड़ित नहीं होगा। जब नेता, विधायक या सांसद, विधानसभा या संसद में गला फाड़कर जनजाति क्षेत्र की निर्धनता से, बेराजगारी से, और अन्य असुविधाओ से अवगत करवा सकता है तो वह सरकार से उन योजनाओं का भंडार भी खुलवाता सकता है। जिनसे जनजाति समाज का व्यक्ति अपने खेत में अपने पानी के साथ खेती, किसानी कर सकेगा।

पलायन पर जाते लोगों के बच्चों के बिगड़ते भविष्य को संवारने के लिए शासन-प्रशासन को जनजाति अंचल में पहली प्राथमिक सुविधा में

रिंकेश बैरागी

जल की व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। भ्रष्ट्राचार करने वाले उन नेताओं को पद मुक्त करना होगा जो अधिकारियों पर दबाव बनाकर तालाव निर्माण, या नहर निर्माण, या फिर बांध निर्माण में झोलझाल करने की छुट दे देते है। कुपोषित होते उन बच्चों की शरीर की सुद्रढ़ता के लिए लोगों के खेतों तक पानी को पहुंचना अत्यधिक आवश्यक है। तभी तो वह सुचारु रुप से खेती कर पाएगा और अपने बच्चों को स्थानीय स्कूल में शिक्षा के साथ पोषण भी व्यवस्थित कर पाएगा। जिले के हर गांव में कहीं नाला, तालाब, पुरानी बावड़ी या नदी है लेकिन उनमें जल संग्रहण की सुचारु व्यवस्था नहीं है। बरसात के बाद ही जिले की नदियों में पानी बह जाता है और वे सुख जाती है। ऐसे ही तालाबो का पानी भी धीरे-धीरे कम हो जाता है। शासन-प्रशासन इन जल स्त्रोतों में पानी के यथावत होने की व्यस्था भर भी कर दे तो पलायन जाते मजदूरों में बहुत कमी होगी और लोग कृषक ही बने रहेगे...।

अडानी को जेल में होना चाहिए- राहुल गांधी

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद के बाहर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2,000 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है। ऐसे में उन्हें जेल में होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार अडानी को बचा रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि जहां सैकड़ों लोगों को छोटे-छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है, वहीं एक 'जेंटलमैन' (गौतम अडानी) पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपये की रिश्वत के गंभीर आरोप हैं, और फिर भी वह आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि अडानी को गिरफ्तार करे और उन्हें जेल भेजे।

राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ÷आपको क्या लगता है, अडानी इन आरोपों को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं। यह स्पष्ट है कि वह इन आरोपों से इनकार करेंगे। लेकिन असल मुद्दा यह है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।÷

उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह सरकार अडानी को बचाने में लगी हुई है और यह साफ दिखता है कि सरकार बड़े व्यापारियों को संरक्षण दे रही है। वहीं आम लोगों को मामूली आरोपों में ही गिरफ्तार किया जा रहा है।

संभल हिंसा पर स्वरा भास्कर की कड़ी प्रतिक्रिया

मुंबई, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हैं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने अब तक 7 मामले दर्ज किए हैं और 27 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इस हिंसा को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और न्यायपालिका अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो रही है। उनका कहना था कि यह स्थिति पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रशासन ने इलाके की सुरक्षा बढ़ाते हुए जिले की सीमाओं को 30 नवंबर तक सील कर दिया है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। संभल के एसपी ने बताया कि हिंसा के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 100 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है और उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग हिंसा में शामिल थे, उन्हें सजा मिलेगी। इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संभल दौरे की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। शहर में प्रवेश से पहले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। हिंसा में घायल पुलिसकर्मी ने 800 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिनमें कई नामजद आरोपी भी हैं। मामले की जांच जारी है।

केजरीवाल के खिलाफ भाजपा की नई रणनीति, मुद्दों पर फोकस

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर प्रचार शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, भाजपा ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए अपनी रणनीति तय करना शुरू कर दी है। भाजपा इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे को घोषित न करने की योजना बना रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और स्थानीय मुद्दों के सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी का मानना है कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ 10 साल की सत्ता विरोधी लहर, खराब सड़कों की स्थिति, यमुना और हवा का बढ़ता प्रदूषण, मुख्यमंत्री आवास पर भारी खर्च, और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। भाजपा का मानना है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करने से गुटबाजी बढ़ सकती है, जैसा कि 2015 में किरण बेदी को उम्मीदवार बनाने के बाद देखा गया था। पार्टी ने हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़कर सफलता पाई है। इस बार भाजपा की योजना सामूहिक नेतृत्व और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की है। पार्टी का जोर दिल्ली सरकार की विफलताओं और अधूरे वादों को उजागर करने पर होगा। शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि मुद्दों पर केंद्रित प्रचार अभियान से भाजपा को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

स्वास्थ्य विभाग की करोड़ों की भूमि अतिक्रमण से हुई मुक्त,न्यायालय के निर्णय के बाद प्रशासन ने की कार्यवाही

ग्रामीणों ने उठाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग

माही की गूंज ,बरवेट।
जगदिश प्रजापत

रायपुरिया थाना क्षेत्र के बरवेट गांव में न्यायालय आदेश पर तहसीलदार हुकुमसिंह निगवाल की अगुवाई में राजस्वकर्मियों व पुलिस की संयुक्त टीम ने शासकीय की जमीन से अतिक्रमण हटवाया।

तहसीलदार हुकुमसिंह निगवाल, नायब तहसिलदार सारंगी अंकिता भिड़े, झकनवाद तहसिलदार संजय गर्ग हल्का पटावरी, मलसिंह डामर, पटवारी आर एस डामर, सचिव रामकिशन वर्मा, रोजगर सहायक जवरसिह डामर, मोबोलाइजर राकेश निनामा, रायपुरिया थाना से एएसआई रामचंद्र बरोठा, रतनसिंह मैडा पुलिस बल के साथ बरवेट में पहुंच गए। जहा हमीरगढ़ मार्ग से लगी आबादी की शासकी भूमि सर्वे क्रमांक 409 की रकबा 8989 वर्ग फ़ीट पर तार फेंसिंग, वाल बाउंड्री, सीमेंट सलिये से निर्मित पिल्ल सहित अन्य तरीके से किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया। इसके बाद जमीन को सरकारी कब्जे मे लेकर ग्राम पंचायत को सुपुर्द की। इस अवसर पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान लगभग पांच घंटे तक चला। यह मामला पिछले पांच सालों से कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाया।

ये था मामला

लगभग छह वर्ष पूर्व जिला कलेक्टर आशीष सक्सेस जिला पंचायत सीइओ जमुना भिड़े, पेटलावद एसडीएम हर्षल पंचोली, जनपद पंचायत सीइओ महेन्द्र धनधोरिया सहित आला अधिकारी मॉर्निंग फॉलोअप के लिए बरवेट पहुंचे थे। जिस पर ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष चौराहे पर सब्जी की दुकाने लगने से यातायात बाधित होता था साथ ही उपस्वास्थ केंद्र निर्माण के लिए भूमि नहीं होने से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। इसके बाद कलेक्टर ने नायब तहसीलदार गजराज सिंह सोलंकी सारंगी को निर्देशित कर तीन दिन में भूमि ग्राम पंचायत को आवंटित की जाए। इस पर नायब तहसीलदार जीएस सोलंकी और पटवारी आरएस डामर बरवेट पहुंचे। ग्राम पंचायत बरवेट के सरपंच अनोखीलाल सिंगाड, सचिव जवरसिंह डामर ग्रामीणों के साथ शासकीय भूमि देखने पहुंचे। तहसीलदार जीएस सोलंकी ने हमीरगढ़ रोड पर आबादी की 409 नंबर की भूमि जो कि रेकॉर्ड में शासकीय थी ग्राम पंचायत बरवेट आवंटित कर दी। इसका प्रतिवेदन पालन एसडीएम और कलेक्टर को भेज दिया। लेकिन मामला कोर्ट में पहुचा गया। कोर्ट का फैसला आने के बाद आज अतिक्रमण हटाया गया।

अब हॉस्पिटल के लिए रास्ता साफ

ग्राम पंचायत बरवेट द्वारा हॉस्पिटल की मांग पिछले दो दशक से की जा रही थी। ग्राम बरवेट में हॉस्पिटल स्वीकृत हो कर टेंडर भी हो चुका था। लेकिन शासकीय भूमि नही मिलने के कारण कार्य अटका हुआ था। रविवार को पेटलावद तहसीलदार हुकुमसिंह निगवाल ने आबादी की सर्वे नंबर 409 से अतिक्रमण हटाकर ग्रामपंचायत को हॉस्पिटल निर्माण के लिए 8989 वर्गफीट भूमि आवंटित की।

प्रथामिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए

उपस्वास्थ्य केंद्र भवन जर्जर होने के बाद शासन ने नया भवन स्वीकृत कर राशि आबंटित की गई लेकिन नए भवन के लिए चयनित स्थान पर विवाद होने और मामला न्यायालय में पहुँचने के बाद भवन निर्माण अधर लटक गया। अतिक्रमण हटने के बाद उप स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी है। लेकिन बरवेट क्षेत्र बड़ा होने की स्थिति में अब ग्रामीणों ने यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की है। भाजपा नेता संजय परमार ने बताया कि बरवेट क्षेत्र में ज्यादा गाँव लगते हैं और लोगों को इलाज की सुविधा के अभाव में पेटलावद ओर रायपुरिया जाना पड़ता है जिससे कई बार मरीजों ओर उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरवेट में प्रथामिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवा कर उसका भवन बनाया जाए इसके लिए केबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया से मांग की जाएगी।

70 प्लस के बनाए जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड, अधिकांश स्थानों पर बनी सर्वर की समस्या

माही की गूंज,सारंगी।
संजय उपाध्याय

इन दोनों 70 प्लस से अधिक उम्र के सभी वृद्ध जनों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जिला कलेक्टर नेहा मीना के आदेशअनुसार बीएमओ डॉक्टर सुरेश कटारा के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि वृद्ध जनों को आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज मिल सके। सारंगी में 301 आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है , जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर-घर जाकर वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। अभी तक 52 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं , इसके लिए कैंप भी लगाए जा रहे हैं। घर-घर जाकर भी प्रतिदिन कार्ड बनाए जा रहे हैं लेकिन कर्मचारियों को कई स्थानों पर सर्वर की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही कई वृद्ध जनों के केवाईसी नहीं होने के कारण भी कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इस कड़ी में अभियान के तहत बीएमओ सुरेश कटारा लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से आयुष्मान कार्ड को लेकर जानकारी ले रहे है साथ ही आयुष्मान कार्ड बनाने में आ रही दिक्कतो को जानकर उन्हें दूर किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सचिव हरिराम भूरिया एवं सुपरवाइजर जगदीश नायक ने बताया कि कार्ड बनाए जाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अमला मैदानी स्तर पर तैनात है घर-घर जाकर भी 70 प्लस हितग्राहियों का कार्ड बनाए जा रहे हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाते वक्त सुपरवाइजर जगदीश नायक, सहायक सुपरवाइजर जगदीश गरवाल, कंप्यूटर ऑपरेटर भगोरा एवं आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इच्छाओं का मार्ग भोग का मार्ग है इन्हें त्याग कर ही आनंद मिलने वाला है - साध्वी श्री अनुपम शीलाजी

माही की गूंज ,पेटलावद।

आहार भय मैथुन परिग्रह ये चार संज्ञा ऐसी है जिसके कारण जीव ने अनंत भवों को खोदीया हैं।जीव ने उनको पाने के अनेक पुरुषार्थ करलिये कि सुख मिलेगा। पर वोतो मृगतृष्णा थी जिसके पीछे भागते ही रहे।ऐसे ही भागते रहे तो मोक्ष कब मिलेगा ? इच्छाओं की पूर्ति में ही भटकते रहे तो आत्मा को मुक्ति कब मिलेगी? इच्छाओं का न और है ना छोर है। इच्छाओं का मार्ग भोग का मार्ग इन्हे त्याग कर हीआनंद मिलने वाला है। इच्छाओं की पूर्ति आत्मा को भटकती है। भवी और भव्य आत्मा ही जिनवाणी को औषधि रूप ग्रहण कर अपना उद्धार कर लेती है । उक्त बात पेटलावद गौरव साध्वी श्री अनुपम शीला जी ने अपनी वरिष्ठ साध्वी श्री धैय प्रभा जी साध्वी श्री सारिका जी साध्वी श्री चतुरगुणाजी पेटलावद गौरव साध्वी श्री आस्थाजी साध्वी श्री अंजलिजी के साथ गृह नगर पेटलावद में प्रवेश करते हुए स्थानक भवन में कहीं । भौतिक साधन सुख चार देते हैं दुख हजार देते हैं। जैसे कार के सुख कम और झंझट ज्यादा है जैसे ड्राइवर पेट्रोल चोरी चालान पंचर आदि आदि।साधनों की वजह से ऐसा लगता है व्यक्ति उसका गिरवी हो गया है । भौतिक साधन कि वासना , उसकी दोस्ती जीवन भर जलाती है । साधन तथाकथित सुख और सपनों के सामान बनकर रह गए हैं । साध्वी श्री चतुरगुणा जी ने कहा परिग्रह के संग्रह में व्यक्ति अपने कर्तव्य भूल जाता है।ममत्व भाव साधना से दूर कर देते हैं । पेटलावद गौरव साध्वी श्री आस्था जी ने कहा कर्म बंधनों से मुक्त होना ही प्रगति है। चार गतियों मे तो हमने कई भव में कर लिये।अब प्रगति करना है सिद्धालय से दूरी घटाना है। सम्यक पुरुषार्थ करके अव्या बाध सुखों को पाना है। प्रातः युवाओं के लिए महावीर कॉलेज का भी संचालन हो रहा है। साध्वी श्री धैर्य प्रभा जी अनुपम शीला जी ठाणा छ बामनिया चातुर्मास संपन्न कर पेटलावद पधारे।

समस्या : कागजों में उलझी किसानों के लिए बनी योजनाएं

माही की गूंज , पेटलावद।

किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पीएम किसान योजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। लेकिन, अभी भी कई ऐसे किसान हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। किसानों की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है, ताकि किसानों को खेती संबंधित और सरकारी योजनाओं से संबंधी समस्याओं को हल किया जा सके, ताकि अधिक से अधिक किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। राजस्व महाअभियान में सबसे ज्यादा जोर किसान रजिस्ट्री (फार्मर आईडी) बनाने पर दिया जा रहा है। लेकिन इसमे कई प्रकार की विसंगतियां आने से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नही बन पा रही है। जबकि राजस्व महाअभियान 15 नवम्बर से 15 दिसंबर तक चलेगा।

फार्मर आईडी के लिए जरूरी कागजात

सरकार की योजनाओं का लाभ सिधे किसानों के देने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसमें किसान के नाम के साथ-साथ, स्वामित्व वाली ज़मीन की खसरा नम्बर, सह-खातेदार होने की स्थिति में किसान का अंश, मोबाइल नंबर, आधार संख्या वगैरह दर्ज करानी होती है। साथ ही फ़ैमिली आईडी भी जरूरी होती है।

नाम मैच नहीं होने से नही बन रही फार्मर रजिस्ट्री

किसान रजिस्ट्री पंजीकरण के लिए खसरा खतौनी में दर्ज किसान का नाम आधार कार्ड में दर्ज नाम मेल नही होने से फार्मर आईडी नही बन रही है। साथ ही भू अभिलेख से आधार ओर मोबाइल नंबर की ईकेवाईसी नही होने पर भी फार्मर रजिस्ट्री नही बन रही है। साथ ही कई किसानों के मोबाइल नही होने से नम्बर भी नही जुड़ पा रहे हैं।

कृषि खाते में नाम अलग ओर बाकी दस्तावेज अलग

ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की सबसे बड़ी समस्या कृषि भूमि के खाते में दर्ज नाम है जो कि उनके बाकी दस्तावेजो में नाम अलग है। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या राजस्व रेकॉर्ड में नाम परिवर्तन नही होता है और बाकी दस्तावेजों में नाम परिवर्तन करवाने पर बैंक खाते सहित अन्य शासकीय रेकॉर्ड प्रभावित होता है। किसान मनोज पुरषोत्तम पाटीदार ने बताया कि इस प्रकार की समस्या मेरे साथ हो रही है और फार्मर आईडी के लिए आधार कार्ड में नाम परिवर्तन का कहा जा रहा है जो सम्भव नही है क्योंकि मेरे सारे शासकीय रिकॉर्ड में आधार में दर्ज नाम ही लिखा हुवा है , राजस्व रेकॉर्ड में थोड़ा सा नाम परिवर्तन होने पर भी पोर्टल पर आईलाइन फार्मर आईडी स्वीकृत नही हो रही ।

कछुआ गति से चल रहा कार्य आखिर ग्रामीणों को कब मिल पाएगा पानी...?

मामलाः थांदला जनपद क्षेत्र की नारेला व तलावड़ा ग्राम पंचायत में जल जीवन जल मिशन का

माही की गूंज, खवासा।

केंद्र व राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन , जल मिशन में ग्रामीणों को शुद्ध जल पहुंचने का दावा 2026 तक सभी घरो में शुद्ध जल पहुंचने का दावा धरातल पर कब पहुचेगा पता नहीं।

मामला थांदला जनपद की ग्राम पंचायत नारेला व तलावड़ा में सामने आया जहां करोड़ों रुपये की लागत से जल जीवन जल मिशन में टंकी बनाने के साथ ही घरों तक पाइपलाईन बिछाने का कार्य कछुआ गति से हो रहा है। तो कुछ जगह कार्य की गति धीमी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार प्रगति कंस्ट्रक्शन कंपनी नई दिल्ली द्वारा कार्य दोनों पंचायत पर किया जा रहा है। दोनों ग्राम पंचायत में अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। जबकि अन्य पंचायत में दूसरी फर्म कंपनियों ने पूर्ण कर दिया है। बताते हैं कंपनी ने कछुआ गति से कार्य शुरू किया है जिसके कारण अभी तक ग्रामीणों को कार्य पूर्ण करके ग्राम पंचायत को सुपुर्द नहीं किया। ठेकेदार को विभागीय अधिकारियों ने सरक्षण दे रखा जिससे कार्य की गुणवता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

ग्राम पंचायत नारेला के ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि, जहां टंकी का निर्माण किया जा रहा है वहां उसका बेस ही कम बनाया है। पथरीली जगह होने के कारण टंकी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, जो कंपनी कार्य कर रही है उसने अभी तक कार्य को पूर्ण नहीं किया है। जिसके कारण आने वाले समय में ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो पाएगा ।

बताते हैं टेंडर अवधि 18 माह की होती है। इसी में ठेकेदार को कार्य पूर्ण करके देना है लेकिन 2021-22 में कार्य शुरू कर अभी तक कार्य पूरा ही नहीं हुआ।

कार्य की गुणवता पर उठने लगे सवाल

मॉनेटिंग करने वाले पीएचई विभाग के अधिकारी कार्यालय में बैठकर ही फाइलों पर साइन करके हरा-हरा दिखा रहे हैं। माही की गूंज ने नारेला ग्राम पंचायत में जल जीवन जल मिशन में कार्य किया जा रहा है जिसका मौके का मुआना क्या तो, वहां पदस्थ कंपनी की तरफ से सब इंजीनियर विशाल लोवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि, कार्य तो अच्छा चल रहा है तराई भी हम तीन दिन में एक बार टैंकर लगाकर करते है। जो कंपनी माल हमें दे रही है उसी आधार पर हम कार्य करते हैं। बाकी आप बताएं कहां कमी लग रही है, उसको भी सही कर दिया जाएगा। जबकि मौके पर न तो टंकी के ऊपर तरी के लिये टाट भी नहीं बिछा कर रखे थे। जबकि तराई करने से पहले टाट लगाकर अच्छी तरह से सीमेंट व रेत को भिगोकर तराई करना है। ताकि मजबूती से टंकी की पकड़ हो सके। लेकिन वहां पथरीली जमीन पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रगति नई दिल्ली द्वारा निम्न व घटिया किस्म का कार्य करके शासन के पैसों की बंदर बाट की जा रही है। जबकि कंपनी के इंजीनियर का दावा भी झूठा साबित हुआ जिससे भ्रष्टाचार की बु आ रही है।

वही तलवाड़ा में चार माह से कार्य बंद है। यही कंपनी वहां भी कार्य कर रही है। तलावड़ा सरपंच प्रतिनिधि कमलेश गेहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि, मेरी पंचायत में भी घटिया व निम्न स्तर का कार्य कर रहे थे लेकिन मैने कार्य को बंद करवा दिया। पीएचई विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया लेकिन ठेकेदार को संरक्षण देते हुए नजर आए। आज दिन तक ठेकेदार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी न ही ठेकेदार को नोटिस आदि दिए की गुणवत्ता के साथ कार्य जल्दी करें। हमारी पंचायत में तो हमने उसको कार्य सही नहीं करने के कारण काम बंद करवा दिया। ग्रामिणों का कहना है कि, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि, इस कंपनी का जहां भी कार्य चल रहा है उसकी जांच की जाए। पीएचई विभाग के अधिकारीको इस और ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से शासन के पैसों की बंदर बाट ठेकेदार कर रहा है।

जिले के पीएचई विभाग की पांचो उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में नजर आ रहा है। बताते हैं की पीएचई विभाग में सब इंजीनियर गौरीशंकर चौधरी साहब थे जिनका ट्रांसफर हो गया था लेकिन झाबुआ के विभागीय अधिकारियों ने रिलीव नहीं करा। क्योंकि उनके सानिध्य में ठेकेदारों की बल्ले-बल्ले और विभागीय अधिकारियों की मलाई चाट रहे थे। काफी दबाव पढ़ने के बाद उनको राजगढ़ जिले के लिए विभागीय अधिकारी ने रिलीव करा है। चौधरी साहब के सरक्षण में ही ठेकेदार को पनाह मिल रही थी और निम्न व घटिया स्तर का कार्य करके ठेकेदार, शासन को चूना लगा रहे थे।

वही मामले मे प्रगति कंस्ट्रक्शन नई दिल्ली के प्रोजेक्ट मैनेजर नितेश चौहान से चर्चा की तो उनका कहना था कि, कार्य तो अच्छा ही हो रहा है आपको फोटो और वीडियो भी बता देंगे। कार्य कछुआ गति पर उन्होंने बताया कि, कई जगह सरपंच ने हमको सही जगह उपलब्ध नहीं कराई, जगह का सही आवंटन नहीं होने के कारण कार्य लेट हुआ है। बाकी जल्द ही कार्य कर दिया जाएगा।

विभाग की सब इंजीनियर कुसुम कवचे से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, आपके द्वारा मुझे जानकारी दी गई है, पूर्व में इनको चौधरी साहब देखते थे अभी मुझे चार्ज नहीं मिला है जैसे ही मुझे चार्ज मिलेगा तो मैं सभी साइड की विजिट करूंगी और जो भी कमी पेशी होगी सुधारने का ठेकेदार को कहा जाएगा।

अब सवाल यह उठता है कि क्या मीडिया जब धरातल पर पहुंच कर जानकारी इनको उपलब्ध कराता है तभी यह कार्रवाई की बात करते हैं?

संपादकीय

जलवायु संकट की अनदेखी

आज ग्लोबल वार्मिंग संकट दुनिया के तमाम देशों के दरवाजे पर दस्तक देकर रौद्र रूप दिखा रहा है। ऐसे में बाकू में संपन्न कॉप-29 सम्मेलन में दुनिया की आबोहवा बचाने की दिशा में ठोस निर्णय न हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। दरअसल, विकसित देश विगत में की गई अपनी घोषणाओं से पीछे हट रहे हैं। वे गरीब मुल्कों को ग्लोबल वार्मिंग संकट से निपटने के लिये आर्थिक मदद देने को तैयार नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि दुनिया पर जलवायु संकट के गंभीर परिणामों से विकसित देश वाकिफ नहीं हैं। अमेरिका से लेकर स्पेन तक मौसम के चरम का त्रास झेल रहे हैं। लेकिन इसके घातक प्रभावों को देखते हुए भी सभी देश समाधान निकालने को लेकर सहमति क्यों नहीं बना पा रहे हैं। कहना गलत न होगा कि विकसित देशों द्वारा अक्सर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन हाथी के दिखाने के दांत साबित हो रहे हैं। दशकों से चले आ रहे सम्मेलनों के बावजूद जलवायु संकट दूर करने के लिये सभी देशों की हिस्सेदारी व जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि कॉप-29 में विकासशील देशों की चिंता व नाराजगी को भारत ने आवाज दी है। भारत ने सम्मेलन में ग्लोबल साउथ देशों का नेतृत्व करके धनी देशों को आईना दिखाया। यह हकीकत है कि धनी देशों के रवैये के चलते विकासशील देश खुद को छला महसूस कर रहे हैं। अपने विकास की कीमत पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने पर सहमत हुए गरीब मुल्क इसके मुकाबले के लिये धनी देशों की मदद की तरफ देख रहे हैं। यह विडंबना है कि अजरबैजान में कॉप-29 सम्मेलन का समापन तल्ख बयानों व असहमति के बीच हुआ। आखिर धनी व गरीब मुल्कों के बीच सम्मेलन के बाद भी अविश्वास का वातावरण क्यों बना हुआ है। निश्चित रूप से यह स्थिति भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिये साझा प्रयासों की संभावना को ही खत्म करेगी।

विगत में विकसित देशों ने वायदा किया था कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास में होने वाले खर्च की पूर्ति के लिये 1.3 ट्रिलियन डॉलर सालाना मदद दी जाएगी। लेकिन अब ये देश मामूली रकम देने को ही तैयार हैं। इससे पर्यावरणीय क्षति को रोकने के प्रयासों हेतु आर्थिक संसाधन जुटा पाना संभव न होगा। वहीं दूसरी ओर इस दिशा में निर्धारित लक्ष्य अपर्याप्त ही हैं। इस गंभीर मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत है। दूसरी विकसित देश सीमित मदद को सीधे देने के बजाय ऋण के रूप में देने की बात कर रहे हैं। जाहिर है कर्ज के साथ शर्तें भी कठोर हो सकती हैं। दरअसल, अपनी पिछली पारी में पर्यावरण संकट पर बेरुखी दिखाने वाले नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी दुनिया के मुल्क असमंजस में हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका क्लाइमेट चेंज प्रभाव को रोकने के लिये धन उपलब्ध कराने में ना-नुकर कर सकता है। भले ही संकट से निपटने के लिये पर्याप्त धन न जुटाया जा सके,लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस मुद्दे में दुनिया के देशों में सहमति बन सके। निस्संदेह, मतभेद मनभेद में न बदलें और दुनिया के तमाम देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबले के लिये एकजुट होने का संकल्प लें। यही वजह है कि भारत ने टूक शब्दों में कहा कि जलवायु संकट से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ विकासशील देशों की ही नहीं है। निस्संदेह, धनी मुल्कों को जवाबदेही से भागने से बचना चाहिए। हालांकि, बाकू में जलवायु संकट पर गंभीर मंथन तो हुआ पर समस्या की गहराई को समझने की ईमानदार कोशिश नहीं की गई। यदि जलवायु वित्त पैकेज पर सहमति बनती तो इससे जुड़े मुख्य मुद्दों के समाधान की राह खुलती। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। यह निर्विवाद सत्य है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिये विकासशील देशों को अपने विकास को धीमा करना पड़ेगा। लेकिन औद्योगिक क्रांति के जरिये प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने वाले विकसित देश अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के बाद विकासशील देशों को ऐसा करने से रोक रहे हैं।

अब सत्ता की चाबी लाडली बहनों के हाथ

टीवी चैनल पर महाराष्ट्र की एक महिला ने कहा कि सरकार की योजना से उसे जो पैसे मिले, उससे वह पहली बार साड़ी खरीद सकी। यह कितने अफसोस की बात है कि जब शादियों में दिखावे के रूप में पांच हजार करोड़ तक खर्च किए जा रहे हों, तब उसी प्रदेश में एक स्त्री इस बात के लिए धन्यवाद दे कि वह जीवन में पहली बार साड़ी खरीद सकी।

जब पिछले दिनों मध्य प्रदेश के चुनाव में वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बहुमत प्राप्त किया था, तो उन्होंने कहा था कि लाड़ली बहनों ने उन्हें जीत दिलाई है। सारा श्रेय उन्हीं को दिया जाना चाहिए।

कल किसी ने जब कहा कि भारतीय जनता पार्टी रेवड़ियों का विरोध करती है और उसने महिलाओं को खूब रेवड़ियां बांटी तो एक अन्य दल की महिला नेत्री ने कहा कि इसे रेवड़ी नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। और महाराष्ट्र कोई गरीब राज्य नहीं कि सरकार जरूरतमंद स्त्रियों की मदद नहीं कर सकती।

स्त्री सशक्तीकरण में स्त्रियों के हाथ में पैसे हों, उनकी क्रय शक्ति बढ़े, वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें, इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसके अलावा स्त्री विमर्श कहता है कि स्त्रियों के नाम अक्सर चल-अचल सम्पत्ति नहीं होती। इसलिए वे हमेशा अपने परिवार के पुरुषों के भरोसे रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने स्त्रियों के नाम से ही पक्के घर दिए हैं। उन्हीं के नाम अगर जमीन की रजिस्ट्री हो तो स्टाम्प ड्यूटी में दो प्रतिशत की छूट मिलती है। इससे पहली बार भारत में स्त्रियों के अपने घर हो सके हैं। अक्सर स्त्रियों को हिंसा झेलते हुए, सबसे पहले घर से निकाला जाता है। अब जब घर उनके ही नाम पर है, जमीन उनकी है, तो किसकी हिम्मत है कि उन्हें घर से निकाल सके।

महाराष्ट्र में इस बार पंद्रह चुनाव क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों से भी अधिक वोट दिए। 65.22 प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया। कुछ स्थानों पर रजिस्टर्ड महिला मतदाताओं की संख्या भी पुरुषों से ज्यादा थी। कुल 30.64 मिलियन वोटर्स में कुल महिला वोटर्स की संख्या 46.99 है। महिला मतदाताओं के बड़ी संख्या में बाहर आने के बारे में बताया जा रहा है कि इसका बड़ा कारण लाड़की (लड़की) बहणी योजना को है। जिसमें महिलाओं को पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह दिए गए और सरकार बनने पर इक्कीस सौ रुपये देने का वादा किया गया। चुनाव में जीत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने भी लाड़ली बहनों का धन्यवाद किया। महाराष्ट्र में स्त्रियों की शिक्षा के लिए आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया गया था।

इसी तरह झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार की वापसी का श्रेय, उनकी स्त्री सम्बंधी योजनाओं को दिया जा रहा है। जिसमें प्रमुख थींकृस्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल मुफ्त देना, एकल मां को आर्थिक सहायता प्रदान करना, बेरोजगार स्त्रियों को मासिक भत्ता, मइया योजना के अंतर्गत गरीब स्त्रियों को साल में बारह हजार रुपये की मदद। इससे गरीब परिवारों और स्त्रियों के जीवन में कुछ खुशहाली आई। आदिवासी इलाकों में इसे विशेष रूप से महसूस किया गया। चूंकि स्त्रियों के खाते में पैसे सीधे भेजे जाते हैं, इसलिए उसका लाभ भी सीधे उन्हें ही मिलता है। इससे उनका परिवार भी लाभान्वित होता है। ऐसी योजनाएं अकेली बेसहारा माताओं, विधवाओं, स्कूल जाती लड़कियों को विशेष लाभ पहुंचाती हैं।

याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने यहां की स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिलें दी थीं। सिर्फ एक साइकिल की सहायता से स्कूल जाने वाली लड़कियों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। चूंकि वे समूह में स्कूल जाती थीं, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर भी माता-पिता की चिंता में कमी आई थी और स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई थी। उनका ड्रॉप आउट रेट भी कम हुआ था। और परिणामस्वरूप इन लड़कियों के माता-पिता ने अगली बार नीतीश कुमार को बहुमत से विजयी बनाया था।

झारखंड में हेमंत सोरेन ने नीतीश कुमार से सीखा और महाराष्ट्र में शिवराज सिंह चौहान से सीखा गया। हेमंत की जीत में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की भी बड़ी भूमिका है। हेमंत सोरेन को जब जेल भेजा गया, तो उनकी पत्नी कल्पना ने मोर्चा संभाला। उन्हें स्त्रियों की खूब सहानुभूति भी मिली।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी स्त्रियों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। जैसे कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम-इसमें ग्रामीण महिलाओं को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन पायलट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे कि वे आधुनिक तकनीकों से खेती कर सकें। इसके लिए उन्हें आर्थिक मदद भी दी जाती है। उड़ीसा में चलाई जा रही सुभद्रा योजना। जिसके अंतर्गत पांच सालों में गरीब महिलाओं को पचास हजार रुपये रक्षाबंधन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिए जाते हैं। महिला सम्मान पेंशन योजना- जिसमें विधवाओं और बूढ़ी महिलाओं को मदद दी जाती है। जिससे कि वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें। अल्पसंख्यक महिलाओं को बिना किसी ब्याज के पचास हजार रुपये की मदद दी जाती है। इसमें से बस पच्चीस हजार रुपये उन्हें वापस देने पड़ते हैं। इसका लाभ तलाकशुदा और अठारह साल से पचपन साल की अविवाहित महिलाएं उठा सकती हैं। इसी प्रकार दिल्ली, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में भी महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली बहुत-सी योजनाएं हैं।

देखने की बात यह है कि औरतों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं, नेताओं को विधानसभाओं और लोकसभा में पहुंचा रही हैं। यह स्त्रियों की ताकत है, जिसे वे वोट के जरिए दिखा रही हैं। वे जानती हैं कि उनके जीवन के लिए ऐसी योजनाएं कितनी जरूरी हैं। लोकतंत्र में महिलाएं गेम चेंजर की भूमिका निभा रही हैं।

इस हिसाब से अगर अमेरिका के चुनाव पर नजर डालें तो वहां बड़ी संख्या में महिलाएं ट्रंप के खिलाफ थीं क्योंकि ट्रंप को गर्भपात का विरोधी माना जाता है। मगर वे चाहकर भी ट्रंप को हरा नहीं सकीं।

क्षमा शर्मा

अपने यहां महिलाएं आगे बढ़कर वोट दे रही हैं। यही नहीं, ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि वे अपने घर के आदमियों की बात भी नहीं मानतीं। वे वहां वोट देती हैं जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सके। इनमें ग्रामीण महिलाएं बड़ी संख्या में होती हैं। अब वह समय चला गया है जब चुनाव विश्लेषक कहते थे कि औरतें वोट देने ही नहीं आतीं। इसमें सरकारों द्वारा चलाए गए उन अभियानों का भी हाथ है जो स्त्रियों से कहते थे चूल्ह-चौका बाद में पहले वोट। क्योंकि एक बार महिला घर के काम में लग जाती हैं तो गए रात तक उन्हें दम मारने की फुर्सत नहीं होती। इसलिए पहले वोट फिर कुछ और।

पिछले कुछ दशकों से भारत में राजनीतिक दलों ने महिलाओं की इस ताकत को पहचाना है। इसलिए वे अपने-अपने मेनिफेस्टो में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हैं। तरह-तरह के वादे करते हैं। और सिर्फ वादे ही नहीं जीतने के बाद उन्हें कुछ हद तक पूरे भी करते हैं।

विकसित देशों की जवाबदेही सुनिश्चित हो

ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियां गंभीर चुनौती बन चुकी हैं, जिसके समाधान हेतु वैश्विक स्तर पर चर्चा की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, दुनियाभर के देश बाकू में आयोजित कॉप-29 सम्मेलन में एकत्रित हुए, जहां इन समस्याओं से निपटने के उपायों पर विचार किया गया। हालांकि, सम्मेलन के पहले सप्ताह के बाद भारत ने यह स्पष्ट किया कि यह समस्या विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए भारी संकट बन गई है, और इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।

समस्या स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास और आधुनिकीकरण के कारण उत्पन्न प्रदूषण यानी कार्बन व हरित गैसों का उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के चलते पर्यावरण में भयंकर परिवर्तन हो रहे हैं। यह समस्या केवल ग्लोबल साउथ (विकासशील देश) के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर संकट बन चुकी है। हालांकि, कुछ वैश्विक उत्तर (विकसित देश) के देश यह मानते हैं कि पर्यावरणीय संकट की जिम्मेदारी सिर्फ विकासशील देशों पर है, और उन्हें ही इसका समाधान करना चाहिए। निस्संदेह, यह गलत सोच है। अब इस समस्या को गंभीरता से स्वीकार करने और समाधान की दिशा में प्रयासों की आवश्यकता है।

भारत ने कार्बन और हरित गैसों के उत्सर्जन को निम्न स्तर पर लाने का संकल्प लिया है, लेकिन वित्तीय संसाधनों और तकनीकी मदद के अभाव में जलवायु परिवर्तन से निपटना बेहद कठिन हो रहा है। ग्लेशियरों का असमय पिघलना, बाढ़ और अनिश्चित मानसून के कारण कृषि संकट में पड़ गई है। कॉप-29 सम्मेलन से यह उम्मीद थी कि दुनिया के सभी प्रमुख देश मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सम्पन्न देशों के नेताओं ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, और न ही भारत सहित अन्य देशों ने मिलकर प्रभावी रणनीति बनाई। इसके बजाय, केवल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा।

बाकू में कॉप-29 शिखर सम्मेलन किसी महत्वपूर्ण सफलता के बिना समाप्त हो गया, जहां विकसित और विकासशील देशों के बीच गहरे मतभेद सामने आए। इस समय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है, ताकि आर्थिक गतिविधियां सुचारु रहें और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ न्यायसंगत कदम उठाए जा सकें। मांग हुई है कि संपन्न देशों को 1.3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर अनुदान और रियायती वित्त सहायता के रूप में देना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि अब तक जितना भी वित्त पोषण हुआ है, वह अधिकतर ऋण के रूप में विकासशील देशों को दिया गया है, जिससे उनकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता पर संकट उत्पन्न हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है।

भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों ने मौसम के पैटर्न को अप्रत्याशित बना दिया है। किसानों के लिए मानसून अब अनिश्चित हो चुका है। इस स्थिति में कृषि की प्रगति नहीं, बल्कि उसका संकट बढ़ता जा रहा है। भारत और अन्य दक्षिणी देशों को जलवायु परिवर्तन के सबसे भयानक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है।

संपन्न देश यह तर्क देते हैं कि कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य जिम्मेदार उभरते हुए विकासशील देश हैं, और इसलिए इन्हें ही इस संकट का सामना करना चाहिए। उनका कहना है कि उनका औद्योगिक विकास और प्रौद्योगिकी अब बदल चुकी है, और वे कृत्रिम मेधा और इंटरनेट का सर्वाधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो गया है।

इस स्थिति में जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रक्रिया केवल भाषणों तक सीमित रह गई है, और असल कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती। भारत ने विकसित देशों से निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक वे वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहायता नहीं देते, तब तक यह प्रयास सार्थक नहीं हो पाएगा। भारत ने यह भी सवाल उठाया कि विकसित देशों के पास पर्याप्त संसाधन और क्षमता होने के बावजूद वे इस वैश्विक समस्या को गंभीरता से क्यों नहीं स्वीकारते।

सुरेश सेठ

भारत और अन्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के भयावह प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इन देशों की अपनी क्षमताएं इस संकट से निपटने के लिए सीमित हैं। यह स्पष्ट है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान विकसित और विकासशील देशों को मिलकर ही करना होगा, क्योंकि इस संकट का असर अंततः सभी देशों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। भारत ने जी-77 देशों के सम्मेलन में भी संपन्न देशों से वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर जवाबदेही की मांग की है। यह सवाल भी उठाया कि कार्बन उत्सर्जन के नियंत्रण की तिथियों को आगे बढ़ाने से क्या हासिल होगा, जब आर्थिक असंतुलन पहले ही सभी देशों के सामने आ चुका है।

स्वराज से सुराज तक संविधान की अमृत यात्रा

भारत का संविधान अपने शानदार 75 वर्ष पूरे कर रहा है, भारत सरकार व देश ने 26 नवंबर से 26 जनवरी तक संविधान की हीरक जयंती मनाने का निर्णय किया है, 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस के कार्यक्रम सम्पन्न हो रहे हैं।

देश का जन संविधान व संविधान की विशेषताएं, संविधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगा व अधिक जागरूकता के साथ जहां अपने अधिकारों व कर्तव्यों को समझेगा। वहीं, संविधान की ताक़त व संवेदनशील मुद्दों को भी आत्मसात? करेगा।

75 वर्ष की इस शानदार यात्रा में भारत एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। दुनिया के बहुत सारे देश भारत को अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। आम भारतीय भी दुनिया के इस नजरिये से अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 देशों का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलना, भारत के सम्मान का द्योतक है। संविधान की 75 वर्ष की यात्रा में संविधान ने अनेक प्रश्नों को झेला है। पुराने क़ानूनों का बोझ, बदलते युगानुरूप नये क़ानून, आपातकाल और उसमें नागरिक अधिकारों की अनुपस्थिति-लोकतंत्र का काला अध्याय, बार-बार तोड़ी गई विपक्षी सरकारें, अल्पमत सरकारों के संकट से संविधान सफलतापूर्वक गुजरा है, सदैव अपने नये कलेवर में संसाधनों के साथ, अधिक तेजस्विता के साथ उपस्थित हुआ है।

पिछले लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक चर्चा में भारतीय संविधान ही था। विपक्ष द्वारा उठाई, संविधान की पुस्तक सर्वाधिक मीडिया की सुर्ख़ियां बनी। एक छद्म विमर्श उपस्थित किया गया संविधान बदलने का। जन मानस पर उसका असर भी दिखाई दिया। लेकिन आज सहज जागरूक नागरिक के रूप में हम भारत के लोग उस विमर्श से सत्य पर आ गये, क्योंकि सत्य हर विमर्श को ढाह देता है। सामयिक संशोधनों के साथ-साथ, भारत का संविधान अपने मौलिक स्वरूप में सदैव अवस्थित रहा है।

आज़ादी का सूरज उदय होने के समय, हमारे संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के सदस्य जुलाई, 1946 में चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसम्बर, 1946 में हुई थी। इसके बाद देश दो भागों भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई - भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 में अपना काम पूरा कर लिया। इसी संविधान प्रारूप लेखन समिति के अध्यक्ष डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की पहली प्रति संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ?. राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित की। 26 जनवरी, 1950 को हमारा यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। जो एक महान पर्व बन गया है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था।

भारत के संविधान का मूल आधार ब्रिटिश भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। इस में लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिये गए हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। दुनिया में शासन बनते ही शासन चलाने के नियम बनाने पड़े, यही नियम आज दुनिया के देशों में संविधान के रूप में है। सदैव एक ही प्रकार के नियमों से संचालन संभव नहीं है, स्थिति के बदलाव के साथ ही नियमों में बदलाव आवश्यक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन का प्रावधान तय किया।

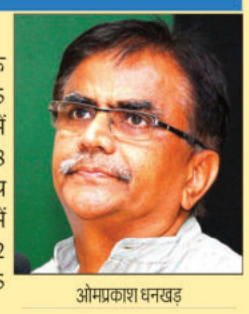

ओमप्रकाश धनखड़

संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी 448 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं।

हमारे संविधान ने अपने मूल रूप में स्थापित रहते हुए, आवश्यक बदलावों को सहज अंगीकार किया है। इन 75 वर्षों में स्वराज से सुराज की यात्रा भारत के संविधान ने की है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की है। सहजता से शासन के बदलाव की परम्परा को क़ायम किया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अखंड रखा है।

भारत के लोगों का संविधान पर विश्वास प्रगाढ़ हुआ है। हम भारत के लोग अपने संविधान के माध्यम से भारत के सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र, मज़बूत लोकतंत्र, सर्वधर्म समभाव, अंतिम व्यक्ति की प्रगति के विशेष अवसरों के साथ-साथ विषमता आर्थिक व सामाजिक विषमता समाप्त करने और राष्ट्र के रूप मे एक विकसित राष्ट्र बनाने में कामयाब हो रहे हैं। भारत के संविधान की देखरेख भारत की अमृत पथ यात्रा की ओर अग्रसर है। संविधान के हर पहलू पर विशेष अध्ययन के रूप में इस हीरक जयंती को हम मनायें।

पहलवान बाबा की दरगाह का हिस्सा हटाया गया

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम के जावरा फाटक से सेजावता फंटे तक बन रहे फोरलेन के निर्माण में पहलवान बाबा की दरगाह का कुछ हिस्सा आ रहा था, जिसे बुधवार को प्रशासन ने हटा दिया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने दरगाह के बाहरी हिस्से को गिरा दिया, जबकि मुख्य मजार को सुरक्षित रखते हुए उसे साफ किया और फूल चढ़ाए।

विवाद और प्रशासन की कार्रवाई

इस मामले में पहले कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे, क्योंकि स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने दरगाह को बचाने की कोशिश की थी। प्रशासन ने पहले मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से बैठक की और उनकी सहमति से एक हिस्सा छोड़ने का फैसला लिया था। लेकिन इसके बाद, कोर्ट में स्टे खारिज होने के बाद, प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया।

स्थानीय लोगों का विरोध

हालांकि, कुछ लोगों का कहना था कि दरगाह को अवैध तरीके से नष्ट करने की कोशिश की जा रही है, और इसे बचाने के लिए मुस्लिम समुदाय द्वारा अदालत का सहारा लिया गया था।

फोरलेन परियोजना

4.12 किलोमीटर लंबे फोरलेन प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से चल रहा है, और यह सड़क परियोजना जावरा फाटक से सेजावता फंटे तक को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। इस निर्माण के कारण कुछ धार्मिक स्थल और अन्य संरचनाओं को हटाना पड़ रहा है।

कोर्ट का एकपक्षीय आदेश और बाद की कार्रवाई

13 नवंबर को अदालत द्वारा दिए गए एकपक्षीय आदेश के बाद, 14 नवंबर को सरकारी अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने कोर्ट में स्थगन आदेश को निरस्त करने की याचिका दी। इसके बाद 26 नवंबर को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 13 नवंबर के स्टे आदेश को निरस्त कर दिया।

इसके बाद, 27 नवंबर को प्रशासन और पुलिस की टीम ने दरगाह पर पहुंचकर, कोर्ट के आदेश के अनुसार, दरगाह के बची हुई हिस्से को हटाने की कार्रवाई शुरू की।

फोरलेन निर्माण के कारण दरगाह का हिस्सा हटाना

रतलाम के जावरा फाटक से सेजावता फंटे तक 4.12 किमी लंबा फोरलेन बनाया जा रहा है। इस निर्माण के चलते, पहलवान बाबा की दरगाह का कुछ हिस्सा और हनुमान मंदिर का भी एक हिस्सा आ रहा था। प्रशासन ने दरगाह कमेटी, शहर काजी अहमद अली और अन्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सहमति बनी थी कि दरगाह के कुछ हिस्से को हटाया जाएगा।

प्रशासन ने इसके बाद दरगाह के आसपास की कुछ दुकानें भी हटाईं, जिनकी स्थिति फोरलेन निर्माण में बाधक बन रही थीं। हालांकि, इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्हें स्थगन आदेश (स्टे) मिल गया था।

कोर्ट में हुआ निर्णय

26 नवंबर को कोर्ट ने स्थगन आदेश (स्टे) को निरस्त कर दिया, जिसके बाद 27 नवंबर को प्रशासन ने दरगाह के बाकी हिस्से को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।

यह विवाद उस समय गहरा गया था, जब मुस्लिम पक्ष ने दरगाह के नष्ट होने के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, हालांकि अब इस मामले में प्रशासन ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्रवाई की है।

सिविल अस्पताल के पीएम रूम में रखे बच्ची के शव की दुर्दशा का मामला

माही की गूंज, शाजापुर।

9 माह की मासूम नन्ही बच्ची जो की अपने कदमों पर भी सही ढंग से नहीं चल पाई थी वह मृत अवस्था में तीन दिवस पूर्व अपनी मां के साथ कुएं में मिली थी। इस मासूम की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने अभी पड़ताल सही रूप में शुरू भी नहीं की होगी और इस मासूम के शव के साथ हुई दुर्दशा का मामला सामने आया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले को छुपाने का प्रयास तो किया लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही छुपाई नहीं जा सकती है। तीन दिवस पूर्व जिस 9 माह की बच्ची का शव सिविल अस्पताल शुजालपुर के पोस्टमार्टम रूम में रखा गया था वह शव अगले दिन सुबह पीएम रूम के समीप बनी नाली में मिला। जिसे कुत्ते नोच रहे थे। कुछ लोगों ने तत्काल कुत्तों से शव को छुड़ाया और उसके बाद डॉक्टर की पैनल में उक्त शव का परीक्षण किया है। पैनल ने अभी अपनी पीएम रिपोर्ट पुलिस को नहीं सौपी है। अस्पताल परिसर में सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं लेकिन उक्त घटना दिवस पर शार्ट सर्किट के चलते कैमरे खराब होना बताया जा रहा है। बता दें कि गुरुवार की शाम को पुलिस थाना मंडी क्षेत्र अंतर्गत डाबरी गांव में 26 वर्षीय आरती पति नरेंद्र शर्मा एवं उसकी 9 माह की बेटी नित्यांशी का शव घर के समीप स्थित कुएं से मिला था।

कैमरे में नहीं सच्चाई

9 माह की बच्ची के शव को पीएम रूम से खीचकर नाली में ले जाने की सच्चाई अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बयां नहीं कर सकते। अस्पताल प्रबंधन की माने तो विद्युत शार्ट सर्किट के कारण कैमरे तीन दिवस पूर्व खराब हो गए थे। बता दें कि इसी अस्पताल में जब झाड़ला गांव निवासी प्रसूता सपना की मौत जिस दिन हुई थी उस दिन के सीसी फुटेज भी अस्पताल प्रबंधन में जांच कमेटी अथवा मीडिया को उपलब्ध नहीं कराए थे। अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि उस दिन के फुटेज डिलीट हो चुके हैं।

पीएम रूम से 9 माह की बच्ची के शव को कुत्ते ले गए थे, यह सुनने में आया है। अब सुधार कर लिया गया है। ऐसा हो सकता है उम्मीद नहीं थी। नाली के रास्ते कुत्तों ने प्रवेश कर लिया था। पहले ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। अब पीएम रूम में जानवर प्रदेश नहीं कर सकें इसके लिए सरिए लगवा दिए गए हैं और व्यवस्था बनाई गई है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे शॉर्ट सर्किट के कारण खराब हो गए थे अब इन्हें दुरुस्त कर लिया गया है।

आबकारी अधिकारी निधि जैन का सुरेश पटेल पर बना है आशीर्वाद, कार्यवाही के नाम पर निधि जैन मोन क्यों ?

माही की गूंज, शाजापुर।

शुजालपुर तहसील में पदस्थ भ्रष्ट व गांधी छाप के हवस के पुजारी सब इंस्पेक्टर सुरेश पटेल के आगे जिला प्रशासन आबकारी अधिकारी निधि जैन भी नतमस्तक दिखाई दे रही है इसका फायदा उठाकर सब इंस्पेक्टर सुरेश पटेल शराब माफियाओं के साथ दिन दुगनी और रात चौगुनी करके पैसा कमाने में लगे हुए हैं इनके निकम्मेपन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शराब जोरों पर बेची जा रही है मगर इस भ्रष्ट के कानो जू तक नहीं रह रही है

गांव गली मोहल्ले और किराना दुकानों में धड़ल्ले से बिक रही अवैध शराब शाजापुर जिले के शुजालपुर तहसील में आबकारी विभाग के संरक्षण में चल रहा अवैध शराब बिक्री का खेल क्षेत्र में अवैध देशी व अंग्रेजी शराब की बिक्री जोरों पर चल रहा है कोई भी गांव हो गली मोहल्ला या किराना में दुकान भले पानी उपलब्ध हो या ना हो देशी शराब बियर व्हिस्की रम जो भी ब्रांड चाहिए बड़े आसानी से उपलब्ध हो रहा है जानकारी के अनुसार सूत्रों का कहना है कि ये शराब सब इंस्पेक्टर किस पर गांव गांव दुकानों पर परोसी जा रही है कोई कुछ कहने वाला नहीं है ना ही किसी का कोई दवाब है जो भी थोड़ा बहुत दबाव बनता है वहां लेनदेन कर सेटिंग से काम चल रहा लेकिन शराब बेचने वाले और शराब सप्लाई करने वाले के लिए आबकारी व पुलिस मानो कोई चीज ही नहीं है जिस पर थोड़ी बहुत करवाई पुलिस विभाग द्वारा की जाती है पर आबकारी विभाग ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र को जानता ही नहीं इसके बावजूद इसकी बिक्री पर ना कोई पाबंदी है ना ही कोई सुध लेने वाला अब देखना है कि आबकारी विभाग क्षेत्र में अवैध तरीके से बिक रही देशी शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही करते हैं या नहीं क्षेत्र की जनता महिला क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए एकजुट होकर शासन से आस लगाए बैठे हैं।

हरियाणा पंजाब की तर्ज पर हुआ ट्रेक्टरों के बीच महामुकाबला

माही की गूंज, शाजापुर।

हरियाणा और पंजाब में ट्रेक्टरों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसी तर्ज पर सलसलाई में विभिन्न कंपनियों के ट्रेक्टरों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें स्वराज, महिंद्रा, सोनालिका व जॉन डियर कंपनी के ट्रेक्टरों के बीच उनकी क्वालिटी का मुकाबला हुआ। कंपनियों की आपसी स्पर्धा को लेकर आयोजित इस प्रतियोगिता में स्वराज कंपनी के ट्रेक्टर की मजबूती और क्वालिटी का लोहा सभी ने माना और विजय हासिल की जिसे प्रथम पुरस्कार दिया गया। उक्त प्रतियोगिता का संचालन आनंद मेवाड़ा ने किया।

हरियाणा और पंजाब के बाद सलसलाई में हुई अनोखी प्रतियोगिता

हरियाणा और पंजाब में इस तरह की प्रतियोगिताएं की जाती हैं। जिसके बाद मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के ग्राम सलसलाई में यह प्रतियोगिता हुई। जहां स्वराज 855 सहित बड़ी-बड़ी कंपनियां इसमें भाग लेती हैं। जिसे टोचन प्रतियोगिता कहा जाता है। जिससे कंपनियों के मॉडल की मजबूती और उपयोगिता का पता चलता है।

आयोजक समिति ने किया विजेता का सम्मान

इस टोचन प्रतियोगिता में स्वराज कंपनी के ट्रेक्टर की जीत हुई। प्रतियोगिता के बाद कंपनी के कर्मचारियों का आयोजक समिति के हरिओम हाड़ा, जितेंद्र मेवाड़ा, शुभम भिलाला, अरविंद मेवाड़ा, मुकेश पुरी द्वारा सम्मान किया गया।

थाना बिलपांक पुलिस ने अवैध शराब से भरा कंटेनर किया जप्त

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के थाना बिलपांक पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल करते हुए 510 पेटी अवैध शराब से भरा कंटेनर ट्रक जब्त किया। जब्त की गई शराब और वाहन की कुल कीमत करीब ?1.22 करोड़ आंकी गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक सुनील कुमार को गिरफ्तार किया, जो हरियाणा के भिवानी जिले का निवासी है।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार खाखा एवं एसडीओपी अभिलाष भलावी के मार्गदर्शन में बिलपांक पुलिस ने यह कार्रवाई की। विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि रतलाम से बदनावर की ओर जाने वाले एक कंटेनर ट्रक में अवैध शराब भरी हुई है। सूचना पर सक्रिय होकर पुलिस ने महू-नीमच हाईवे पर वाहनों की चेकिंग शुरू की और संदिग्ध ट्रक (क्रमांक एनएल 07 एए 3565) को रोका।

जांच के दौरान ट्रक में 510 पेटी अवैध शराब पाई गई। ट्रक चालक से शराब के परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शराब और ट्रक को जब्त कर लिया। थाना बिलपांक में इस मामले पर प्रकरण क्रमांक 668/24 के तहत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया कि शराब हरियाणा से अकोला, महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी। इस कार्रवाई ने अवैध शराब के कारोबार पर कड़ा प्रहार किया है और जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों का भी पर्दाफाश किया जा सके।

सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को कार ने मारी टक्कर,मौत

माही की गूंज, शाजापुर। अकोदिया सलसलाई थाना क्षेत्र के मदाना जोड़ पर शनिवार सुबह 9 बजे के लगभग एक 50 वर्षीय बुजुर्ग बस से उतरकर सड़क पार कर रहा था तभी तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे ज्ञान सिंह नामक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही डायल 100 मौके पर पहुंच कर बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाया। सलसलाई थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक ज्ञान सिंह पिता भंवर सिंह 50 वर्षीया निवासी मदाना गांव का बताया जा रहा है। वही कार सवार युवक घटनास्थल से फरार हो गया था, जिसे सारंगपुर के पास स्थानीय निवासी एवं डायल 100 पुलिस की मदद से पकड़ा घटनास्थल पर पहुंची। डायल 100 की टीम आरक्षक नितेश सेन,पायलट जगदीश सोनी ने मौके पर पहुंचकर मृतक बुजुर्गों का शव सारंगपुर अस्पताल पहुंचाया गया है। सलसलाई पुलिस ने कर को जब्त कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शाला मे अनियमित आने वाले बच्चो पर शिक्षक ध्यान दे - कलेक्टर सुश्री बाफना

माही की गूंज, शाजापुर।

कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने मो. बड़ोदिया जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम मदाना एवं सलसलाई का भ्रमण कर विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर, अनुविभागीय अधिकारी गुलाना सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, कार्यपालन यंत्री पीएचई विजय सिंह चौहान, सीएमएचओ डॉ. अजय सालविया, जनपद सीईओ अमृतराज सिसोदिया, तहसीलदार श्रीमती वंदना हरित सहित स्थानीय सरपंचगण उपस्थित थे।

ग्राम मदाना में कलेक्टर सुश्री बाफना ने कन्या प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 01 से 03 के लिए चल रही एफएलएन गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए शिक्षक को निर्देश दिये कि शाला में अनियमित आने वाले एवं अनुपस्थित बच्चों पर विशेष ध्यान दें। यहां उपस्थित सरपंच गोविंद मालवीय से कलेक्टर ने कहा कि वे ऐसे बच्चों के माता-पिता को शिक्षा का महत्व बताएं और बच्चों को शाला में भेजने के लिए प्रेरित करें। कलेक्टर ने उपस्थित बालिकाओं से जोड़-घटाव एवं किताबें पढ़वाई, बच्चों के बेहतर प्रदर्शन पर कलेक्टर सहित सभी ने ताली बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

मदाना एवं सलसलाई में कलेक्टर ने राजस्व महाअभियान 3.0 के तहत किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने पटवारियों को निर्देश दिये कि वे आधार को राजस्व भू-अभिलेख (आरओआर) से लिंक करने की कार्यवाही में तेजी लाएं। कलेक्टर ने यहां उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि वे जल एवं मकान कर पंचायत में जमा कराएं, इससे उन्हें ग्राम पंचायत की अन्य सुविधाएं प्राप्त होने लगेगी। कलेक्टर ने सरपंचों से कहा कि वे बड़े काश्तकारों द्वारा शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने में राजस्व अधिकारियों का सहयोग करें। व्यक्तिगत द्वेश के आधार पर अतिक्रमण नहीं हटाएं, छोटे एवं गरीब लोगों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर परेशान नहीं करें। कलेक्टर ने अतिक्रमण से मुक्त होने वाली भूमि पर जल संरक्षण के लिए संरचनाएं बनाने या सामुदायिक उपयोग में लेने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सभी ग्रामीणों से कहा कि वे बटवारा कराकर अलग-अलग खाता बनवाएं और नक्शे में तरमीम करा लें, इससे उनका राजस्व रिकार्ड दुरूस्त रहेगा।

कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड का महत्व ग्रामीणों को बताया

कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने ग्राम मदाना एवं सलसलाई में ग्रामीणों से चर्चा कर आयुष्मान कार्ड के महत्व को बताया। कलेक्टर ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, इससे बुजुर्गों को बीमारियों के उपचार के लिए 5 लाख रूपये तक की सहायता प्राप्त होगी। कलेक्टर ने सभी बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिये। जिन बुजुर्गों के आधार अंगूठे से सत्यापित नहीं होने के कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे बुजुर्गों की फेस रीडिंग से बायोमेट्रिक सत्यापन कर आयुष्मान कार्ड बनाएं।

आंगनवाड़ी पोषण वाटिका को विकसित करें

कलेक्टर सुश्री बाफना ने ग्राम मदाना की आंगनवाड़ी क्रमांक-3 का निरीक्षण करते हुए महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी पंकज दवे एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को निर्देश दिये कि आंगनवाड़ी में पोषण वाटिका को विकसित कराएं। साथ ही बच्चों की आंगनवाड़ी केन्द्र में नियमित उपस्थिति रखें। विद्यालय पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित कराएं।

गौशाला का निरीक्षण

कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने ग्राम मदाना की गीतांजली कामधेनु गौशाला का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने गौशाला संचालक से कहा कि गोबर से जैविक खाद बनाकर विक्रय करें और गौशाला की आमदनी बढ़ाए। कलेक्टर ने यहां गौ-पूजन भी किया।

सोयाबीन उपार्जन का निरीक्षण

कलेक्टर सुश्री बाफना ने ग्राम ईमलीखेड़ा के जेडी इंटरप्राईजेस वेयरहाऊस में चल रहे सोयाबीन उपार्जन कार्य का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने एफएक्यू मापदण्ड की ही सोयाबीन खरीदी करने के निर्देश दिये। साथ ही कलेक्टर ने खरीदी गई सोयाबीन के उठाव के लिए भी भारत सरकार को पत्र लिखने के निर्देश जिला विपणन अधिकारी श्रीमती जेनीफर खान को दिये। कलेक्टर ने बताया कि किसानों को सोयाबीन का भुगतान भी शुरू हो गया है।

न्यूज ब्रीफ

कपास चोरी के विवाद में हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

माही की गूंज, बड़वानी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी एमके जैन ने 01 अक्टूबर 2023 को हुई हत्या के मामले में आरोपी सुनील उर्फ सोनिया को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी ने 8 दिन पहले कपास चोरी करते पकड़े जाने पर रंजिशवश जगदीश को चाकू और दराते से हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आरोपी को धारा 302 के तहत दोषी पाया गया। प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक वेस्तासिंह चौहान ने की, जबकि लोक अभियोजक दीपक चौहान ने पैरवी की।

आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

माही की गूंज, खण्डवा।

राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत विकासखंड पुनासा और छैगांवमाखन की आशा सहयोगियों को बुधवार को सी.एम.एच.ओ. कार्यालय के सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण सत्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने आशाओं से जनसमुदाय को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और कॉलेजों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जागरूकता के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। इस दौरान जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. योगेश शर्मा ने प्रजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया।

खेलों एमपी यूथ-गेम्स 2024 का होगा शुभारंभ

माही की गूंज, खण्डवा।

खेलों एमपी यूथ गेम्स 2024 का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा खेलों इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा। प्रभारी अधिकारी जिला खेल और युवा कल्याण आर.जी. बांगरिया ने बताया कि विकासखण्ड स्तर पर चयन ट्रायल 5 दिसम्बर से 12 दिसम्बर के बीच होंगे। जिला स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन 13 से 15 दिसम्बर के मध्य किया जाएगा। जिले से चयनित खिलाड़ी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। ब्लॉक स्तर से ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही ऑफलाइन फार्म भी ब्लॉक समन्वयक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

प्रभारी अधिकारी जिला खेल और युवा कल्याण बांगरिया ने बताया कि 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक-बालिका (31 दिसम्बर 2024 की स्थिति में) भाग ले सकेंगे। 19 खेलों जैसे कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, कुश्ती, मलखम्ब, बॉक्सिंग, हॉकी, जूडो, तैराकी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, टेबल टेनिस, योगासन, टेनिस, शतरंज को जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 6 खेलों जैसे ताईक्वांडो, आर्चरी, शूटिंग, क्याकिंग कैनोइंग, रोइंग, फेंसिंग का आयोजन सीधे राज्य स्तर पर किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर टीम और एकल खेल में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप प्रथम स्थान पर 31 हजार रुपये, द्वितीय पर 21 हजार रुपये, और तृतीय व चतुर्थ को 11-11 हजार रुपये दिए जाएंगे।

मिला 1155 मे.ट. डीएपी उर्वरक

माही की गूंज, बुरहानपुर।

उपसंचालक कृषि एम. एस. देवके ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में यूरिया का स्टॉक 4692 मीट्रिक टन, एनपीके 2881 मीट्रिक टन, एमओपी 3562 मीट्रिक टन तथा सिंगल सुपर फॉस्फेट 4051 मीट्रिक टन उपलब्ध है। उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता हो रही है और किसानों को सतत रूप से वितरण किया जा रहा है। जिले में खंडवा रैक पॉइंट से उर्वरकों की निरंतर आपूर्ति हो रही है, साथ ही बुरहानपुर रैक पाइंट से भी आज डीएपी उर्वरक 1155 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ। इसमें से 500 मीट्रिक टन सहकारी समितियों नेपानगर, बुरहानपुर को, तुकईथड़ मार्केटिंग फेडरेशन के नगद विक्रय केंद्रों को 250 मीट्रिक टन, एमपी एग्रो को 50 मीट्रिक टन तथा निजी विक्रेताओं को 355 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है। जिले में समस्त प्रकार के कुल 16395 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है।

एक के बाद एक बड़े सड़क हादसे, दुर्घटना में 7 से ज्यादा लोग घायल

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले में मंगलवार को दो बड़े सड़क हादसे हुए, जिनमें सात लोग घायल हो गए। पहला हादसा भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम रूईगढ़ा के पास हुआ। यहां एक तेज रफ्तार कार सड़क से उतरकर बैरिकेट्स को टक्कर मारते हुए खड़े ट्रक से टकरा गई। घटना सुबह करीब 4 बजे की है, जब 8 लोग क्रेटा कार में सवार होकर देवास से सांवरिया सेठ के दर्शन करने जा रहे थे।

चालक और सभी युवक शराब के नशे में

कार के चालक संजय और अन्य युवक शराब के नशे में थे। हादसे में कार में सवार 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि 3 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद देवास भेजा गया। घायल अखिलेश ने बताया कि हादसा तब हुआ जब वे उज्जैन से देवास लौट रहे थे और भैरवगढ़ के रास्ते से गुजर रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घायलों को कार से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी।

तेल से भरा टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलटा

दूसरा हादसा नागझिरी थाना क्षेत्र में हुआ, जहां मंगलवार शाम एक सरसों के तेल से भरा टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। टैंकर ने तीन बिजली के पोल तोड़ दिए, जिससे आसपास के इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। यह टैंकर इंदौर से मक्सी की ओर जा रहा था, और टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर चालक कैशव राजपूत को मामूली चोटें आई हैं, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस दोनों हादसों की जांच में जुटी

दोनों हादसों में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, और पुलिस जांच में जुटी है। स्थानीय लोग और प्रशासन ने हादसों को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है।

कलेक्टर ने ली राजस्व विभाग की बैठक

माही की गूंज, खरगोन।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बड़वाह में राजस्व अनुविभाग के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों की बैठक लेकर राजस्व महा अभियान 3.0 की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर सत्यनारायण दर्रे, बड़वाह एसडीएम प्रताप कुमार अगास्या, डिप्टी कलेक्टर पूर्वा मंडलोई और जनपद सीईओ कंचन डोंगरे भी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर शर्मा ने पटवारी हल्का वार राजस्व महा अभियान के बिंदुओं की समीक्षा की, जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खसरा से आधार लिंकिंग, फार्मर रजिस्ट्री, परंपरागत रास्तों का चिन्हांकन और नक्शा शुद्धिकरण। उन्होंने कहा कि बड़वाह अनुभाग की प्रगति राजस्व महा अभियान-3.0 में सबसे कम पाई गई है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। पटवारियों को अपने कार्यों में सक्रियता दिखाने और शीघ्रता से प्रकरणों का समाधान करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने सभी पटवारियों को कहा कि वे अपने हल्के के किसानों को समझाएं कि आधार लिंकिंग अनिवार्य है और यह किसान योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक है। साथ ही, सभी पात्र किसानों की ई-केवाईसी शत प्रतिशत होनी चाहिए। बैठक में पटवारियों को निर्देश दिया गया कि वे गांव के सचिव, रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम से समन्वय कर किसान रजिस्ट्री का कार्य युद्धस्तर पर करें।

रोल प्रेक्षक की बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया पर चर्चा

माही की गूंज, खंडवा।

जिले के लिए रोल प्रेक्षक के रूप में नियुक्त जॉन किंग्सली ए.आर. ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और 6 जनवरी 2025 को होने वाले मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन पर चर्चा की।

कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के नए मतदाता निर्वाचक नामावली में अपना नाम जोड़ सकते हैं। 28 नवंबर तक नाम जोड़ने, हटाने, त्रुटि सुधारने और दावा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। सभी दावे-आपत्तियों का निराकरण 24 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर के.आर. बड़ोले, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर.सी. खतेड़िया और अन्य निर्वाचन अधिकारी भी उपस्थित थे।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत हुआ शपथ ग्रहण

माही की गूंज, बड़वानी।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत वन स्टॉप सेंटर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज से बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा अभियान की शुरुआत की गई और कार्यक्रम में दिल्ली के विज्ञान भवन से राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़कर सहभागिता की गई।

जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक अजय गुप्ता और परियोजना अधिकारी कविता चौहान ने अधिकारियों और कर्मचारियों को बाल विवाह रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की शपथ दिलाई। ममता संस्था के जिला समन्वयक शैलेश बैरागी ने बाल विवाह के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला और इसके बच्चों की शिक्षा और विकास पर नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की।

इस कार्यक्रम के आयोजन में आस, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन जिला समन्वयक संजय आर्य का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। अभियान के तहत जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाकर बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में संविधान पर पोस्टर और पेंटिंग प्रतियोगिताएं

माही की गूंज, बड़वानी।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा संविधान के निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्राचार्य डॉ. वीणा सत्य के मार्गदर्शन में पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में दो दिवसीय पोस्टर और पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पोस्टर का विषय था - संविधान का महत्व और पेंटिंग का विषय था - संविधान के जनक डॉ. भीमराव आंबेडकर। कार्यक्रम का समन्वय करने वाली कार्यकर्तागण डॉ. प्रीति गुलवानिया और वर्षा मुजाल्दे ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में 25 युवाओं ने अर्थपूर्ण पोस्टर और सुंदर चित्र बनाए। इनका निर्णय डॉ. मीनाक्षी पँवार, डॉ. अभिलाषा साठे और डॉ. धीरज कुमार वर्मा ने किया। पोस्टर प्रतियोगिता में भोला बामनिया प्रथम, खुशी अग्रवाल द्वितीय और सागर भुगवड़े तृतीय स्थान पर रहे। पेंटिंग प्रतियोगिता में अश्विनी जाधव प्रथम, विनिका गेहलोत द्वितीय और राजकुमार सोलंकी तृतीय स्थान पर रहे। आयोजन में सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं में राहुल भंडोले, वर्षा मालवीया, बादल धनगर, संजु डुडवे, भोला बामनिया, खुशी अग्रवाल, नागर सिंह डावर, कन्हैया लाल फूलमाली और डॉ. मधुसूदन चौबे का योगदान रहा।

बालिकाओं को किया पुरस्कृत

माही की गूंज, खरगोन।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर के मार्गदर्शन में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीकनगांव में विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों के तहत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 26 नवंबर को अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति भीकनगांव एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश केके निनामा द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाली 18 बालिकाओं को पुरस्कार वितरण किया गया। जिसमें से प्रथम कुमारी आस्था पिता बसंत यादव कक्षा 10वीं, द्वितीय कुमारी तनीषा पीपल्दे कक्षा 10वीं एवं तृतीय स्थान कुमारी सलोनी गौड कक्षा 12वीं को शील्ड मय प्रशस्ति पत्र एवं शेष भाग लेने वाली प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।

प्लेसमेंट ड्राइव में 35 युवाओं का चयन

माही की गूंज, धार।

शासकीय आई.टी.आई. धार में बुधवार को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजनान्तर्गत प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीथमपुर की प्रमुख कंपनियों कमर्शियल सिन बेग और फ्लेक्सी जेनरिक ने 35 युवाओं का चयन ट्रेनी और अपरेंटिसशिप के लिए किया।

कंपनी के एच.आर. प्रबंधक योगेन्द्र चौधरी और योगेन्द्र पांडे ने बताया कि चयनित युवाओं को बस और मेस सुविधा प्रदान की जाएगी। शासकीय आई.टी.आई. के प्रभारी प्राचार्य अनिल कुमार राजोरिया ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर सतीश डोडिया, प्रिया दाभोलकर, अनूप सिंगार, जगदीश मौर्य, हरीओम अहिरवार, दर्शन सूर्यवंशी, इनेश सोलंकी, विजय बैगा, प्रियंका दुबे, अशरफ हुसैन, अंशुल दांगी, योगेन्द्र और संजय पाल ने इस प्लेसमेंट ड्राइव में महत्वपूर्ण सहयोग किया।

कलेक्टर का निरिक्षण व किसानों से फॉर्मर रजिस्ट्री कराने के लिये की चर्चा

माही की गूंज,झाबुआ।

कलेक्टर नेहा मीना द्वारा विकासखंड झाबुआ के आंगनवाड़ी केंद्र करडावद बड़ी एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण कर केंद्र के बाहर उपस्थित किसानों से की चर्चा। आंगनवाड़ी केंद्र करडावद बड़ी में बच्चों को दिया जा रहे भोजन की गुणवत्ता को देखा गया। कलेक्टर द्वारा समूह द्वारा बनाए गए लड्डू गुणवत्ता की जांच कर बच्चों को लड्डू खिलाया गया। यहां 6 माह से 3 वर्ष के 42 बच्चे, 3 से 6 वर्ष के 45 बच्चे, 10 गर्भवती महिलाएं, 11 धात्री महिलाएं, एक कुपोषित बच्चा व मेम में एक बच्चा पंजीकृत है। कलेक्टर द्वारा कुपोषित बच्चें का वजन कराया गया। पहले से बच्चों में काफी सुधार देखा गया है। बच्चें की नियमित मॉनिटरिंग होने से वह जल्द ही कुपोषण से मुक्त हो जाएगा। सेम बच्चों का प्रोफाइल कार्ड नहीं पाए जाने से संबंधित सुपरवाइजर को नोटिस देने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ ही मोटी आई से चर्चा कर बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने को कहा गया। जो बच्चा कुपोषित है उसकी हार्ट सर्जरी हुई थी। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा उसकी स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखने को कहा तथा उसकी माता को तीन बच्चे होने पर नसबंदी कराने के लिए प्रेरित किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सीडीपीओ को बच्चों को एल्बेंटाजोल की गोली देने को कहा गया। कलेक्टर द्वारा आयुष्मान कार्ड मे प्रगति लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर द्वारा किसानों से फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में चर्चा कर किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराने हेतु जागरूक किया गया। किसानों द्वारा बताया गया कि, राशन की दुकान 3दिन तक नहीं खोली जाती है जिसमें उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि ऐसी दुकान जो 10 दिन से अधिक समय से नहीं खुली। दुकानों के सेल्समैन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिले में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत सभी किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर किसान की एक यूनिक आईडी बनाई जाए, जिससे उसे कृषि योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके और प्रशासन को किसानों से जुड़ी सभी जानकारी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो।

एसडीएम ने किया सोयाबीन उपार्जन केंद्र का निरीक्षण

माही की गूंज, खरगोन।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन बीएस कलेश द्वारा सोयाबीन उपार्जन केंद्र तिरुपति बालाजी बलवाड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने सोयाबीन खरीदी की व्यवस्था का जायजा लिया और किसानों से चर्चा भी की। उन्होंने किसानों से कहा कि सोयाबीन को अच्छी तरह से सूखा कर और साफ करने के बाद ही विक्रय के लिए लेकर आएं। समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी एफएक्यू मानक के अनुसार ही की जाएगी। इस दौरान सहायक संचालक प्रकाश ठाकुर भी उपस्थित थे।

मंत्री गौतम टेटवाल ने मंच से पढ़ा कलमा, मामले ने पकड़ा तूल

माही की गूंज, भोपाल।

उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भाजपा की प्रचंड जीत के लिए भले ही पार्टी के बड़े नेताओं के 'बटेंगे तो कटेंगे' के नारे को गेमचेंजर माना जा रहा हो लेकिन दूसरी तरफ मध्यप्रदेश में मोहन सरकार के मंत्री विवादों में घिर गए है। मोहन कैबिनेट में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल का एक कार्यक्रम में मंच पर कलमा पढ़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।

हिंदूवादी संगठनों ने मंत्री के मंच से कलमा पढ़े जाने पर आपत्ति जताई है। हिंदूवादी संगठन संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मंत्री का मंच से कलमा पढ़ना उचित नहीं है और उनका संगठन इसका विरोध करता है। चंदशेखर तिवारी ने कहा कि मंत्री ने कभी किसी मंदिर में आरती होने के समय अपना कार्यक्रम नहीं रोका होगा और न शामिल हुए होंगे। लेकिन मंत्री को अजान सुनाई पड़ गई तो उन्होंने मंच से ही कलमा ही पढ़ लिया। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि इस कृत्य के लिए मंत्री गौतम टेटवाल को हिंदूओं से माफी मांगनी चाहिए।

इसके साथ ही चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि मंत्री को यह पहले से सुनिश्चित करना था कि अजान के समय कहीं कार्यक्रम तो नहीं हो रहा आप अपने कार्यक्रम को अजान के पहले या बाद में कर लेते लेकिन मंच से कलमा पढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि यह सरकार हिंदू वादीसरकार है सांप्रदायिक सोहार्द बनाकर आप हिंदू समाज को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आप उनके प्रति कितने भी समर्पित हो जाए लेकिन यह आपको कभी भी अपना वोट देकर विजई नहीं करेंगे।

क्या है पूरा मामला

उज्जैन के प्रभारी मंत्री और राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल रविवार को अपने गृह जिले राजगढ़ के सारंगपुर विधानसभा में विकास कार्यों का भूमिपूजन करने गए थे। कार्यक्रम में मंत्री जब मंच से अपना भाषण दे रहे थे तभी कार्यक्रम स्थल के पास ही स्थित मस्जिद में नमाज होने लगी, नमान शुरु होते ही मंत्री ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया और मंच पर कलमा पढ़ा। नमाज खत्म होने के बाद मंत्री ने मंच से अपना भाषण फिर शुरु किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि वो कहता है कि उससे डरो वो एक है, नेक काम करो, और संस्कृत में सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत श्लोक का उच्चारण किया और कहा कि दुनिया में सब लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, शांति से रहें, ये वो भी कह रहा है और हम भी कह रहे हैं,लेकिन सुनने वाले सुन नहीं रहे हैं। राज्यमंत्री गौतम टेटवाल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक तरफ लोग मंत्री के अंदाज की तारीफ कर रहे है वहीं हिंदू संगठन मंच से मंत्री के कलमा पढ़े जाने के विरोध में आ गए है।

महंगाई का असर होटल व्यवसाय पर व्यवसाई एक जुट हुए

माही की गूंज, आम्बुआ।

क्षेत्र में जिधर देखो उधर बस एक ही चर्चा वह केवल और केवल मंहगाई की हो रही है पेट्रोल डीजल गैस आदि के कारण अन्य सामग्रियों में बेतहाशा कीमतों में बढ़ोतरी का असर होटल व्यवसाय में भी पड़ता नजर आ रहा है। मजबूरन इन व्यवसायियों ने एक जुट होकर भाव बढ़ाने का निर्णय लिया और अब ग्राहकों की सामत आई।

होटल व्यवसाय चाहे बड़ा व्यापारी हो या फिर छोटा ठेला गाड़ी पर धंधा करने बाला हो बढ़ती मेहंगाई ने सभी की कमर तोड कर रख दी ,तेल ,बेशन, मिर्च पाउडर,मशाला? हल्दी, एवं गैस के साथ ही कारीगरों तथा मजदूरी के भाव आदि अनेक कारणो से दिनों दिन बढ़ती मेहंगाई ने इन व्यवसायियों को भी परेशान कर दिया। मजबूरन इन व्यवसायियों ने एक जुट होकर भाव बढ़ाने पर विचार किया तथा आज 25 नवंबर से पोहा मिर्ची, कचोरी, समोसा चाय , नमकीन आदि उत्पादनो के भाव बढ़ाने का निर्णय लिया है।

गूंज संवाददाता को होटल व्यवसाय करने वाले व्यापारियों कमल भूरिया, दीपक परिहार, प्रताप सिंह, राकेश राठौड़, योगेन्द्र भूरिया,मोहन, दशम चौहान आदि ने बताया कि बढ़ती मेहंगाई के कारण सभी ने एक जुट होकर भाव बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इंदौर उज्जैन के सड़क मार्ग को सिक्सलेन में बदले जाने का काम शुरू

माही की गूंज, उज्जैन।

आगामी 2028 वर्ष में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व को सफल बनाने के लिए सरकार न केवल कार्यों को अंजाम दे रही है वहीं आने वाले लोगों को भी आवागमन सुगम कराने के लिए चिंता पाली जा रही है और यही कारण है कि इंदौर उज्जैन के सड़क मार्ग को सिक्सलेन में बदले जाने का काम भी शुरू कर दिया गया है।

सिंहस्थ के दौरान इंदौर से उज्जैन आने वाले लोगों की तादात बहुत होगी। इधर सिक्सलेन कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है वहीं रोड के बीच में आने वाले पेड़ पौधों को भी हटाने का काम किया जा रहा है और इन्हें किनारों पर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) के अधिकारियों के अनुसार अन्य कार्य भी तेजी से शुरू किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 19 सितंबर को परियोजना का भूमिपूजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन आकर किया था। 46.475 किलोमीटर लंबे उज्जैन-इंदौर फोरलेन सड़क मार्ग को दो वर्ष के भीतर सिक्स लेन में बदलने की कमान उदयपुर की रवि इंफ्राबिल्ड कंपनी को 735 करोड़ रुपये में सौंपी है। योजना अनुरूप सिक्स लेन सड़क 15 साल के ऑपरेशन-मेंटेनेंस के साथ उज्जैन में स्थित हरिफाटक पुल से इंदौर में स्थित अरविंदो अस्पताल के सामने तक बनाई जाएगी। निर्माण हाइब्रिड वार्षिकी पद्धति से पेव्ड शोल्डर के साथ होगा। मुख्य सड़क डामर की और आबादी क्षेत्र में एप्रोच रोड सीमेंट-कंक्रीट की बनाई जाएगी। फिलहाल रोड किनारे भराव और मध्य में काम शुरू करने से पहले पेड़-पौधों को हटाया जा रहा है। डीपीआर में काफी संशोधन किया गया है। पहले योजना अमल में लाने को 1.35 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने, आठ फ्लाईओवर और 70 अंडरपास बनाना प्रस्तावित था, मगर बाद में जमीन अधिग्रहण करना निरस्त किया और मार्ग में दो वृहद पुल, दो फ्लाई ओवर, छह अंडरपास बनाना तय किया। उज्जैन को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों में यही वो रोड है जहां सर्वाधिक दुर्घटनाएं भी होती है। बीते वर्ष 2023 में इस पर 226 दुर्घटनाएं हुई थीं जिनमें 210 लोग घायल हुए थे और 22 की मृत्यु हो गई थी।

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए ग्रामीणों को दी समझाइश एवं सीएचओ एवं सचिव को दिये निर्देश- एसडीएम

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी तपीस पांडे ने अनुविभाग के भ्रमण के दौरान ग्राम धनपुर एवं घोंधसा में ग्रामीणों से चर्चा कर आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु सचिव, जी.आर.एस., मोबिलाईजर, सी.एच.ओ. एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता से सम्पर्क कर आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु ग्रामीणों को समझाइश दी गई की 70 वर्ष से अधिक आयु वाले हितग्राहियों के शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाये जाने एवं पटवारी को ई-केवाईसी, एफ. आर संबंधी कार्य में प्रगति लाने के संबंध में हल्का पटवारी को आवश्यक निर्देश दिये।

अनुविभागीय अधिकारी तपीस पांडे द्वारा बीईओ कार्यालय अलीराजपुर एवं महिला एवं बाल विकास विभाग अलीराजपुर का निरीक्षण किया जिसमें बीईओ कार्यालय में 14 मे से 08 कर्मचारी एवं महिला बाल विकास कार्यालय में 16 में से 11 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए जिसकी जांच कर भ्रमण के दौरान उक्त निरीक्षण के प्रतिवेदन तैयार कर मुख्यालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किए गए है।

राजस्व महा अभियान का हो प्रभावी क्रियान्वयन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

प्रभारी तथा अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने इंदौर में संभाग के जिलों में पदस्थ कलेक्टर्स और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति, राजस्व प्रकरणों के निराकरण और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा संभागीय बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन की जिलेवार समीक्षा की। इस अवसर पर संभागायुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर के साथ संभाग के जिलों के अन्य कलेक्टर्स और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने राज्य शासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान 3.0 की प्रगति की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यह तय किया जाए कि इस अभियान का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। राजस्व महा अभियान के तहत किये जा रहे कार्यों जैसे- सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, परम्परागत मार्गों के चिन्हांकन, नक्शे में बटांकन, आधार से खसरे की लिंकिंग, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन आदि की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व महा अभियान के प्रत्येक बिन्दु के तय लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।

बैठक में श्रीवास्तव ने ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति की भी जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), मध्यप्रदेश आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत अभियान आदि की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के फलियों में पेयजल की विशेष व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण उपयोगिता वाले क्षेत्रों में ही किया जाए। यह शौचालय ऐसे क्षेत्रों में बनाये जाए जहां आवाजाही अधिक हो। यह शौचालय बाजारों में ज्यादा उपयोगी हो सकते है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना की प्रगति की समीक्षा भी की। श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इंदौर में ली गई संभागीय बैठक में दिए गए निर्देशों के प?रिपालन की भी समीक्षा की।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कार्यक्रम का दिल्ली विज्ञान भवन से महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रसारित सीधा प्रसारण महिला बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर सुश्री प्रियांशी भंवर के साथ देखा। इस दौरान जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एवं बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्यरत एनजीओ के सदस्य भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से बाल विवाह रोकथाम के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन एवं महिलाओं के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार का भी है, जिससे लोगों ने जागरूकता बढ़े।

इस दौरान सभी अधिकारीगण एवं प्रतिभागियों ने बाल विवाह रोकथाम की प्रेरित करने वाली डॉक्यूमेंट्री भी देखी। कलेक्टर डॉ बेडेकर ने इसके पश्चात बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के प्रति जागरूकता प्रसारित करने एवं इस प्रकार की कोई भी गतिविधि रोकने के उद्देश्य से बाल विवाह रोकथाम शपथ का वाचन किया।

कलेक्टर डॉ बेडेकर ने बताया कि शासन द्वारा प्रारंभ किया जा रहा ये अभियान बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त कर देश के बच्चों को एक सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।कार्यक्रम में दिल्ली के विज्ञान भवन से 'बाल विवाह मुक्त भारत' पोर्टल का भी अनावरण किया गया, जो बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने, इसकी रोकथाम करने तथा बाल विवाह की घटनाओं की प्रभावी सूचना देने के अभियान के मिशन के लिए समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने बाल विवाह उन्मूलन के प्रति समर्पण का संकल्प लिया।

हम होंगे कामयाब पखवाड़ा महिला सुरक्षा संवाद रथ को हरी झण्डी दिखाकर रथ का किया शुभारंभ

माही की गूंज, धार।

हम होंगे कामयाब अभियान के तहत् जेडर आधारित हिंसा को रोकने हेतु प्रदेश के समस्त जिले में यह 16 दिवसीय अभियान का आयोजन किया जा रहा है। उसी संदर्भ में बुधवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा हम होंगे कामयाब पखवाडा महिला सुरक्षा संवाद रथ को हरी झण्डी दिखाकर रथ का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास से जिला कार्यक्रम अधिकारी सुभाष जैन, सहायक संचालक भारती डाँगी एवं प्रवीण सिटोले व विभाग का समस्त स्टॉफ उपस्थिति रहा। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग से पर्यवेक्षक ओमिका डावर एवं वन स्टॉप सेंटर की काउसंलर चेतना राठौर द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र-छात्राओं को बाल विवाह निषेध कानून के बारे में एल.ईडी. के माध्यम से जानकारी दे कर जागरूक किया गया। साथ ही इससे होने वाले दुष्परिणाम के बारे में विस्तार से समझाएं दी गई।

संविधान दिवस पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना वाचन एवं विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर के.एन. सिंह के मार्गदर्शन में क्रांतिकारी शहीद छितुसिंह किराड, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अलीराजपुर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आर.पी. सेवेतिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुभाष चौधरी जिला विधिक सहायता अधिकारी, राजेश राठौर लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा सहभागिता की गई।

संविधान दिवस के अवसर पर आर.पी. सेवेतिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुभाष चौधरी जिला विधिक सहायता अधिकारी, राजेश राठौर लीगल एड डिफेंस काउंसिल तथा महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अल्पना बारिया, प्राध्यापकों, अन्य स्टाफ व छात्र-छात्राओं द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया।

जिसके पश्चात् विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्री आर.पी. सेवेतिया ने विद्यार्थियों को बताया कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा की ओर से भारत के संविधान के तैयार खाके को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान के रूप में लागू किया गया था। मौलिक अधिकार और कर्तव्य भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12-35 में दिए गए है। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व विकास में मदद करते हैं और उसकी गरिमा की रक्षा करते हैं। मौलिक कर्तव्य देश के प्रति भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी है, जो संविधान के अनुच्छेद 51(ए) में दिए गए हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों को साइबर क्राइम के बारे में भी जानकारी दी गई।

जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी के द्वारा भारतीय संविधान एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में छात्र-छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया कि संविधान नियमों और कानूनों का एक समूह है, जो किसी देश के संचालन और नियंत्रण को विनियमित करता है। भारत सरकार के राजनीतिक सिद्धांत, अभ्यास और शक्तियां संविधान पर आधारित है। संविधान कर्तव्यों के साथ-साथ मौलिक अधिकारों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और नागरिक जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करता है। संविधान दिवस, संविधान में लिखे मूल्यों, जैसे - न्याय, समानता और भाईचारे की याद दिलाता है। यह नागरिकों में उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढाता है, उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल राजेश राठौर द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अल्पना बारिया, प्राध्यापकगण व अन्य स्टाफ, छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। उक्त जानकारी जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा दी गई।

अवैध शराब से भरी इनोवा पकड़ी, भागने के प्रयास में सड़क से उतरी कार, चालक फरार

माही की गूंज, करवड़।

सोमवार को पुलिस को मिली मुखबीर सूचना पर रतलाम तरफ से एक इनोवा कार नंबर एमपी 04 टीए 4780 में अवैध शराब होने की सूचना मिली। मुखबीर सूचना तस्दीक के लिए चोकी करवड़ से एएसआई जगदीश नायक, हेड कॉन्स्टेबल विजेन्द्र यादव, आरक्षक हर्ष खेमा रतलाम रोड पहुंचे। ग्राम कुंडाल तक पहुचे थे कि, रतलाम तरफ से उक्त नंबर की इनोवा कार आते दिखी जिसे रोकने का प्रयास किया पर चालक द्वारा नही रोकी गई। तथा पुलिस को देख कार को तेज गति से भागने लगा। जिसके कारण ग्राम मोर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गाड़ी खेत मे उतर गई। गाडी क्षतिग्रस्त होने से चलने जैसी नही रही और चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने कार की जांच की तो इनोवा कार के अंदर 26 पेटी माउन्ट 6000 स्ट्रांग बियर कीमत 80 हजार रुपये ओर इनोवा कार कीमत 12 लाख रुपये की जप्त की गई। पुलिस ने चालक के विरुद्ध थाना पेटलावद पर अपराध नंबर 485/24 धारा 34(2)36 आबकारी एक्ट का दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

ठेकेदार के लोग लगे हुए थे पीछे

शराब पकड़े जाने के बाद पुलिस अपनी कहानी बता रही है और माल मुखबिर की सूचना पर पकड़ना बता रही है। लेकिन मामले में क्षेत्र के शराब ठेकेदार के लोगो की भूमिका सामने आ रही है । सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रतलाम क्षेत्र के रानीसिग गाँव से उक्त इनोवा कार के पीछे दो से तीन वाहन लगे हुए थे और उनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर मे अंधगति से भाग रही इनोवा मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से उतर गई। आसपास खेत मे काम कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि, वाहन के पीछे दो से तीन वाहन थे जिनमें 10 से 15 लोग थे ।

फर्जी बैंक : बड़ी ठगी का मामला उजागर

शिकायत के बाद जब तक पुलिस पहुंच पाती चिड़ियां चुग गई खेत

माही की गूंज, झाबुआ। मुज्जमिल मंसुरी

हम हमेशा कहते आए है कि, पश्चिमी मध्यप्रदेश का आदिवासी बाहुल क्षेत्र हमेशा से ही ठगी, भ्रष्टाचार और माफियागिरी का अड्डा रहा है। इस आदिवासी बाहुल क्षेत्र के भोले-भाले आदिवासी आमजनों को हमेशा से ही किसी न किसी तरह से ठगी का शिकार होते देखा गया है। कभी मलटी लेवल मार्केटिंग (चैन सिस्टम) तो कभी बैंक द्वारा लोन के नाम पर की गई धोखाधड़ी, तो कभी बैंक द्वारा उस लोन की उगाही जो कभी लिया ही नहीं गया हो। कभी भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसकर ठगी, तो कभी सूदखोरों के ब्याजी दलदल में फंसकर ठगी। कुल मिलाकर झाबुआ-आलीराजपुर के ज्यादातर गरीब आदिवासी हमेशा ही किसी न किसी ठगी का शिकार होते है। अब इस ठगी का एक पायदान और आगे बढ़ चुका है। सरकारी योजनाओं और बैंक खाते खुलवाने के लिए दस्तावेजों के साथ लाइन लगाकर खड़े रहने की आदत ने आदिवासियों को फिर एक बार बड़ी ठगी का शिकार बना दिया है। आदिवासी क्षेत्र के इन ग्रामीणों को लाइन में लगने की आदत इस कदर लग चुकी है कि, वे इस बात का निर्णय लेने की क्षमता भी गवा चुके है कि क्या सही है और क्या गलत। इसी आदत ने फिर एक बार झाबुआ-आलीराजपुर जिले के सैकड़ों आदिवासियों को ठगी का शिकार बनाया है।

वैसे तो इन आदिवासी जिलों में कई तरह की ठगी आदिवासियों से होती रही है, लेकिन इस बार एक नया पैतरा देखने को मिला है। सीधे तौर पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन व दस्तावेजों के बैंक का संचालन इस बार ठगी का जरिया बना है। आश्चर्य इस बात का भी है कि, झाबुआ जिला मुख्यालय पर ठगोरों ने एक अवैध बैंक का संचालन शुरू किया। विज्ञप्ति जारी कर कर्मचारियों की भर्ती की गई और प्रशासन को कानोकान खबर तक नहीं लगी। नतीजा यह हुआ कि, महज 11 दिनों में 11 लाख से अधिक की ठगी को अंजाम देने का मामला अभी जानकारी में सामने आ रहा है पर असल कितनी बड़ी ठगी हुई है यह तो पुलिस की अपनी निष्पक्ष कार्रवाई के साथ ही सामने आ सकता है। इस तरह की अवैध बैंक झाबुआ जिला मुख्यालय के अलावा थांदला व आलीराजपुर जिले के जोबट में भी संचालित हुई। लेकिन किसी भी प्रशासनिक अमले या अधिकारी को इनकी कोई भी जानकारी या भनक तक नहीं लगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि, सरकारी तंत्र किस तरह की मुस्तैदी दिखाकर अपनी कार्यप्रणाली व कर्तव्यों को अंजाम दे रहा है। शिकायत के बाद पुलिस पहुंची और दबिश भी दी लेकिन उस समय तक चिड़िया खेत चुग चुकी थी।

शिकायत पर पुलिस ने दी दबिश

सोमवर को जिला मुख्यालय पर उस समय हड़कंप वाली स्थिति बन गई जब पुलिस ने एक अवैध बैंक पर छापामार कार्रवाई कर दी। हालांकि पुलिस ने यह कार्रवाई भी किसी ठोस शिकायतकर्ता की शिकायत पर की थी। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। हो सकता था कि, अगर शिकायतकर्ता पुलिस में शिकायत नहीं करता तो आने वाले समय में और भी बड़ा ठगी का मामला सामने आ सकता था। क्योंकि प्रशासन को खुद अपने स्तर पर इस तरह की फर्जी बैंक संचालन की कोई जानकारी नहीं थी। बताया यह भी जा रहा है कि, इस फर्जी बैंक के एजेंट पिछले 2 महीनों से फिल्ड में कार्य कर रहे थे, जो भोले-भाले आदिवासियों को खाता खुलवाने और लोन देने का लुभावना सपना दिखा रहे थे। हालांकि बाद में इस फर्जी बैंक में काम कर रहे कर्मचारी भी ठगी की शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। इन सभी कर्मचारियों को अधिक वेतन देने का लालच देकर काम पर रखा गया था। जब पुलिस, जिला मुख्यालय पर रंगपुरा स्थित इस फर्जी बैंक पर दबिश देने पहुंची उसके पहले ही मैनेजर व उसके साथी अपनी किराए पर ली गई कार से फरार हो गए। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

रूपये लेकर मुख्य आरोपी हुआ फरार

बताया जाता है कि, 15 नवम्बर को जिला मुख्यालय पर इस बैंक की शुरूआत जेएच कैशबीन निधि लिमिटेड के नाम से हुई थी। तभी से लगातार इस फर्जी बैंक में खाता खुलवाने वालों की भीड़ लग रही थी। कतार बद्ध होकर आदिवासी महिलाएं इस फर्जी बैंक में खाता खुलवाने के लिए रोज आ रहे थे। हर व्यक्ति से खाता खुलवाने के लिए 1550 रूपए की राशि जमा करवाई जा रही थी। महज कुछ ही दिनों में यहां सैकड़ों लोगों ने अपने खाते खुलवाकर पैसा जमा करवा दिया था। पुलिस दबिश के पहले ही मैनेजर रूपए लेकर फरार हो गया। झाबुआ में इस पूरे मामले में झारखंड निवासी अखिलेश को मुख्य सरगना बताया जा रहा है जो कि फरार है। इसके अलावा पुलिस ने फर्जी बैंक के कार्यालय से मेहुल पिता संजय परमार निवासी नड़ियाद (गुजरात) तथा अंकित पिता रमनभाई पटेल निवासी मौरेया अहमदाबाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब ठगी की पूरी राशि और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है।

फर्जी बैंक में कार्यरत कर्मचारी भी पहुंचे ठगी की शिकायत लेकर

बैंक फर्जी होने की खबर मिलने के बाद मंगलवार को यहां नौकरी पर लगे एरिया मैनेजर, सर्कल मैनेजर और मैनेजर सहित सभी एजेंट मंगलवार को थाने पहुंचे। फर्जी बैंक में कार्यरत एजेंटों ने और भी कई नाम अपनी शिकायत में पुलिस को बताए है जो गुजरात और राजस्थान के है। इन लोगों ने बताया कि, वे सभी दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में काम कर रहे थे। बैंक वालों ने अधिक वेतन देने की बात पर हमें रखा था। 10 दिन पहले बैंक ने काम की शुरूआत की थी। एजेंटों ने बताया कि, समूह हमें समूह लोन के लिए लोगों को जोड़ना था। 11 महिलाओं का एक समूह बनाकर 1550 रूपए लेकर उनके खाते खोलना थे। खाते खुलने के बाद हर समूह को 7 लाख 70 हजार रूपए लोन देने का लालच दिया गया। मतलब हर खाता धारक को 70-70 हजार रूपए का लोन। हालांकि यह लोन अब तक किसी भी समूह को दिया नहीं गया।

मालिकों ने खुद ढूंढ ली अपनी कारें

फर्जी अवैध बैंक के सरगना ने अपनी फर्जी बैंक के कामकाज के लिए तीन कार किराए पर अनुबंध कर बैंक में लगाई थी। कार मालीकों को यह बताया गया कि, हमें ड्रायवरों की जरूरत नहीं है। हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। जब सोमवार को पुलिस ने इस फर्जी बैंक पर दबिश दी तो मुख्य आरोपी सहित अन्य लोग ये तीनों कार लेकर फरार हो गए। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात में यह कारें अलग-अलग जगह से मिली। जिसमें एक कार दाहोद रेलवे स्टेशन तो दूसरी मेघनगर रेल्वे स्टेशन की पार्किंग व तीसरी झाबुआ बायपास पर मिली। विडम्बना यह कि, इस मामले में पुलिस ने कार मालिकों की कोई सुनवाई नहीं की। तीनों कार मालिकों ने अपने वाहन खुद ही ढूंढ लिए।

कार मालिकों का कहना है कि, उन्हे जब पूरे मामले की जानकारी हुई तो वे अपने वाहन की तलाश में निकले, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो सका। जिसके बाद थाने पर जाकर शिकायत करने की कोशिश की तो थाने से यह कहकर रवाना कर दिया गया कि, तुम्हारी सुने या इन सब लोगों की...! बाद में देखते है... जरूरत पड़ी तो तुम्हे बुला लेंगे। जिसके बाद कार मालिकों ने अपनी गाड़ी को ढूंढना शुरू किया और वे उसमें सफल भी हो गए। हालांकि मेघनगर रेल्वे स्टेशन पर खड़ी कार को लेने पहुंचे मालिक और पार्किंग वालों में काफी बहस हुई। जिसके बाद कार मालिक ने झाबुआ थाने पर संपर्क किया। थाने से दो जवान कार मालिक के साथ पहुंचे और पार्किंग से कार निकलवाकर कार मालिक को सुपुर्द कर दी। मगर इस पूरे मामले में ना तो कार मालिको की कोई सुनवाई हुई और ना ही किसी तरह की कोई लिखा पढ़ी थाने पर की गई। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस, फर्जी बैंक के इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही होगी...? जबकि कारों का रेलवे स्टेशन पर मिलना आरोपियों तक पहुंचने की बड़ी कड़ी हो सकता था। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे चैक कर के यह पता लगाया जा सकता है कि, फरार आरोपी कब, कहां का टिकट लेकर किस ट्रेन में बैठकर कहां तक गया है।

एसबीआई का नाम बड़ा पर बैंक कर्मचारी काम कर रहे खोटा

मामला: प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही ठगी

माही की गूंज, खवासा। सुनील सोलंकी।

इन हितग्राही से भी प्रोजेक्ट रिर्पोट के नाम से वसुली बड़ी राशि।

शासन, युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए कई नित नई योजनाए ला रही है। लेकिन जैसे ही योजना लागू होती है वैसे ही भ्रष्ट अपनी कमाई का जरिया उसमें निकाल लेते है। यानी की योजना का लाभ असल हितग्राहीयो को तो बाद में मिलता है लेकिन भ्रष्टो की जेब पहले ही भरनी होती है। ऐसे में हम पहले भी बता चुके हैं कि, मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का नाम दे दिया है।

तमाम योजनाओं के साथ जनजाति वर्ग के युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए एक योजना 2023 में तात्कालिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना लागू की। उक्त योजना का लाभ 18 वर्ष से 45 वर्ष तक आयु के सिर्फ जनजाति वर्ग ही लाभ ले सकते हैं। योजना में 50 हजार से 50 लाख तक का लोन जनजाति विभाग से मंजूर हो सकता है। उक्त लोन किसी भी व्यापार या मिनी उद्योग स्थापित करने हेतु जनजाति वर्ग इस योजना का लाभ ले सकता है। उक्त योजना के तहत लोन लेने वाले को बैंक ब्याज से कम दर पर मिलता है जो की 5 प्रतिशत सालाना पर है।

उक्त लोन प्राप्त करने के लिए हितग्राही को ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना होता है और जाति प्रमाण पत्र के साथ उपयोगी दस्तावेज के साथ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अधिकतम 15 सौ से 2 हजार तक कर सलाहकार या सीए बनाकर दे देता है। ऐसे में उक्त योजना में एक बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रोजेक्ट के नाम पर 13 हजार से 20 हजार रुपये तक की वसूली की जा रही है का मामला सामने आया है।

भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत झाबुआ जिले के खवासा क्षेत्र के युवाओं ने भी कम ब्याज दर पर सात वर्ष के लिए मिलने वाले इस लोन को लिया जा रहा है। लोन जनजाति विभाग से 2 लाख से 5 लाख या उससे ऊपर के भी मंजूर हुए हैं।

माही की गूंज के सामने जो मामले सामने आए हैं उसमें 2 लाख से 5 लाख तक के लोन हितग्राहियों के हैं। जिसमें खवासा एसबीआई बैंक शाखा क्रमांक 30180 में पदस्थ एक बैंक कर्मचारी जिसके पास लोन डिपार्टमेंट का चार्ज है जिसका नाम पवन मीणा बताया जा रहा है। उक्त कर्मचारी पवन मीणा, बैंक मैनेजर वीरसिंह कुंडल 15 दिनों की छुट्टी पर होने के चलते अभी प्रभारी मैनेजर का कार्य संभाल रहे हैं। ऐसे में पवन मीणा लोगों को तो कह रहे हैं कि, मैं उदयपुर (राजस्थान) से आया हूं और लोगों की सेवा कर रहा हूं लेकिन लोग मुझे सेवा नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन साहब सेवा नहीं बल्कि मेवा खाने का कार्य खुलेआम कर रहे हैं। एसबीआई का नाम तो भले ही बड़ा है लेकिन उसके कर्मचारी काम खोटा कर बैंक की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और यह मामला पहला भी नहीं है, पहले भी एसबीआई बैंक के कर्मचारियों की मनमानियां कई बार उजागर हुई है।

भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत हितग्राहियों से भ्रष्ट प्रभारी मैनेजर पवन मीणा योजना के अनुसार हितग्राहियों से लोन मंजूर हुई राशि का 20 प्रतिशत मार्जिनमनी भरवा रहे हैं जिसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से सभी हितग्राहियों से बिना किसी मापदंड के अपनी मनमर्जी से पैसा तय कर 13 हजार से लेकर 20 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं और कह रहे हैं कि, सीए द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के इतने रुपए ले रहा है। एक हितग्राही के दो लाख मंजूर हुए उसमें 16 हजार रुपये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम पर लिए। वही एक हितग्राही के 3 लाख 20 हजार रुपये का लोन बैंक दे रही है उस पर 13 हजार 5 सौ रुपये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से लिए।

उक्त रुपया भ्रष्ट प्रभारी मैनेजर पवन मीणा अपने निजी बैंक अकाउंट में या नगदी ले रहा है। वही एक हितग्राही के 5 लाख के लोन पर 18 हजार रुपए लिए गए। इसी तरह संगीता तेरसिंह कटारा, भारत राणा मुलथानिया, किशन कटारा सेमलिया आदि जो भी हितग्राही उक्त योजना का लाभ ले रहे हैं और लोन एसबीआई शाखा खवासा से ले रहे हैं उन सभी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम पर अवैध रूप से रिश्वत के तौर पर ही लिया जाना ही सामने आ रहा है।

इस संबंध में माही की गूंज कार्यालय से पवन मीणा को 8319 321441 पर फोन कर बात की, तो कहा मैं अभी फील्ड में हूं और उक्त मामले में बैठकर बात करेंगे। जबकि भ्रष्ट प्रभारी मैनेजर फील्ड में नहीं बल्कि बैंक में ही थे। जब स्थानीय प्रतिनिधि बैंक में साहब से जानकारी लेने गए, तो साहब ने मंजूर किया कि हा मैने इतनी-इतनी राशि हितग्राहियों से ली है यह सही है। लेकिन यह राशि मेरे द्वारा सीए को दी जा रही है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है। मैं, तो लोगों की सेवा करने उदयपुर राजस्थान से आया हूं लेकिन लोक सेवा नहीं करने दे रहे हैं।

अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बताने वाला भ्रष्ट प्रभारी मैनेजर की कही बात की हकीकत जानने के लिए पेटलावद के एक कर सलाहकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के संबंध में कितना रुपया लिया जाता है जाना। कर सलाहकार ने बताया, हमारे द्वारा 5 लाख से अंदर लोन राशि के प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर 1 हजार और 5 लाख से ऊपर 50 लाख तक की लोन राशि होने पर 15 सौ रुपये लिए जा रहे हैं और जो भी हितग्राही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहता है उक्त राशि में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमसे बनवा सकता है।

ऐसे में साहब की रिश्वतखोरी का खुलेआम खुलासा होता है कि, सेवा करने की बात करने वाले पवन मीणा साहब, सीए के नाम पर मोटी रिश्वत वसूल कर मेवा झाड़ रहे हैं।

प्रतिनिधि ने, मीणा साहब से उस सीए का नाम व मोबाइल नंबर मांगे जिसके नाम से साहब वसूली कर रहे हैं। लेकिन ठंड के मौसम में चल रहे पंखे के नीचे बैठे मीणा साहब पसीने में तर-बतर होते दिखे और प्रतिनिधि को कहां, मैं माही की गूंज कार्यालय के नंबर पर उक्त सीए का नाम व मोबाइल नंबर डाल दूंगा। लेकिन साहब ने समाचार लिखे जाने तक भी नाम व नंबर नहीं डाले। और तय है यह भ्रष्ट मैनेजर जो बैंक की प्रतिष्ठा को धूमिल तो कर ही रहा है साथ ही जिस सीए के नाम को भी बदनाम कर रहा है उस सीए का नाम व नंबर आगे भी मीणा साहब नहीं बताएंगे यह तय है। लेकिन पूरे मामले में ऐसे भ्रष्ट अपने बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध एसबीआई क्या कार्रवाई करती है यह देखा दिलचस्प रहेगा।

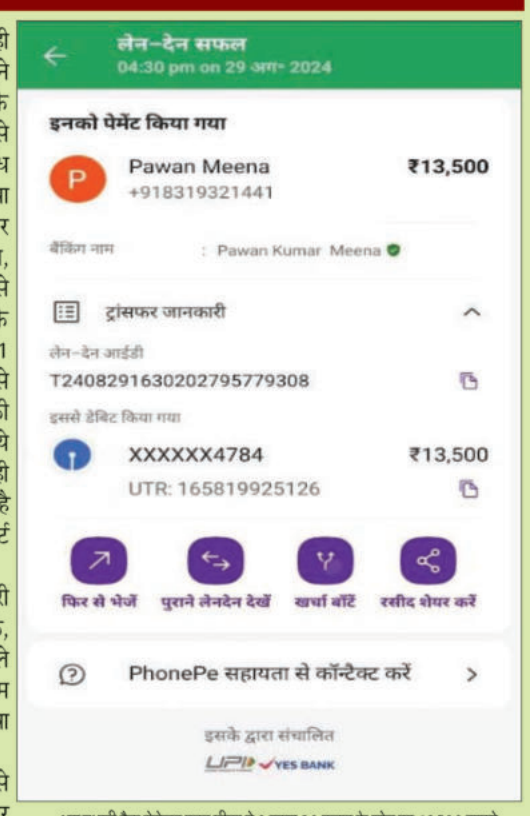

भ्रष्ट प्रभारी बैक मेनेजर पवन मीणा ने 3 लाख 20 हजार के लोन पर 13500 रूपये प्रोजेक्ट रिर्पोट के नाम से अपने निजी बैक खाते में हितग्राही से प्राप्त की राशि।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422